



Sonam Bajwa  
Warns Against...

नौकरशाही



डॉ. त्रजेश मिश्र

वनांचल में एक हाकिम के साथ कुछ ऐसा हो गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काफी जतन से अपने लिए ऐसा ठिकाना तय कराया था, जिससे जिंदगी में कुछ हरियाली आए। काम बन भी गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कालवक्र ने धोखा दे दिया। अब हाकिम बौखलाए घूम रहे हैं।  
आखिर क्या चल रहा है अंदरखाने, जानें द फोटोन न्यूज के एक्जीक्यूटिव एडिटर की कलम से।

SARAF

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| सोना  | : | 14,730 |
| चांदी | : | 295.00 |

(नोट : सोना 22 केरट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

चीन की कोयला खदान में  
ब्लास्ट, 90 लोगों की मौत

**NEW DELHI :** चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा चीन में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक विस्फोट शांक्सी प्रांत के किनयुआन काउंटी में हुआ। यह इलाका बीजिंग से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ समय बाद जोरदार विस्फोट हुआ। जिस समय धमाका हुआ, उस वक्त खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। अभी यह साफ नहीं है कि कितने लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। हेरान्नी की बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद शिन्हुआ ने शुरूआती रिपोर्ट में सिर्फ आठ मौत की जानकारी दी थी और कहा था कि 200 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाद में अज्ञात मृतकों की संख्या बढ़कर 82 बताई गई। सरकारी मीडिया ने यह साफ नहीं किया कि आकड़ा इतनी तेजी से कैसे बढ़ा।

मोदी से मिले अमेरिकी  
विदेश मंत्री मार्को रुबियो

**NEW DELHI :** बार दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। पीएम मोदी ने मुलाकात को लेकर बताया कि श्री मार्को रुबियो का स्वागत करके मुझे खुशी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत-यूएस व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। रुबियो ने भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत अन्य सीनियर अफसर भी मौजूद रहे।

इन दिनों एक साहब बड़े बेचैन हैं। कभी हसरतें उफान मारती थीं, अब हाशिए पर पहुंच चुकी हैं। सारे अरमान टूट कर बिखर गए हैं। कहां तो यह उम्मीद थी, कुछ भला होगा। कुछ बड़ा होगा। पर, किसे पता था, सिर मुड़ते ही ओले पड़ेंगे। सब कुछ एक सपने की तरह टूट गया। गर्मी के मौसम में जिस झरोखे से ठंडी हवा आने के इंतजार में टकटकी लगी थी, अचानक उस पर झांप गिर गया। गुरु की कथा निर्बाध चल रही थी। कथा के मुख्य पात्र के नाम को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। गुरु के सामने सीधा प्रश्न रखा। कौन हैं यह जनाब? गुरु थोड़ी देर मौन रहे। चाय की प्याली आहिस्ता से नीचे रखी। कहा- महोदय, पहले लाल आतंक वाले जनपद के मुखिया थे। व्यवस्था परिवर्तन में गुपचुप तरीके से स्थान परिवर्तन का योग बन गया। अभ्रक नगर नया ठिकाना बना। आनन-फानन में हवाई सफर पर भार उठा लिया। लगा अब दिन बदलने वाले हैं। माहोल में हरियाली होगी। लेकिन यह क्या? हुआ ठीक उल्टा। कुर्सी संभालते ही सब



प्रतीकालक रूप से एआई से बनाई गई कार्पाणिक तस्वीर

कुछ हवा हो गया। छानबीन करने पर पता चला, पुराने सू्रमा ने अनुपस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। गोपनीय में बैठकर गुप्त तरीके से सब गुपचुप कर डाला। सुना है, इन दिनों हजूर के पास करने को कुछ खास नहीं है। लिहाजा स्वभाव के विपरीत खखुआए हुए घूम रहे हैं। बात-बात पर त्योरी चढ़ रही है। कहीं का गुस्सा, कहीं और निकल रहा है। अधीनस्थ मूड देखकर माजरा बताने की

हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गुरु को थोड़ा कुरेदा। कहा- गुरु, 'हर कोई अपने लिए कुछ बेहतर सोचता है, आखिर कुछ लोग इसमें बाधक क्यों बन जाते हैं?' गुरु बोले- ईश्या का अंश मानव स्वभाव का मूल तत्व है। कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। जब जिसके हाथ में लाठी रही, भैस उसी की। पुरखों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई होगी। इसके पीछे लंबा अनुभव रहा होगा। यह दुनिया ऐसी ही है। कुछ लोग रस में आगे रहने की जोर-जुगत में रहते हैं, तो कुछ दूसरों की टांग खींचने में। कई लोग इस ताक में रहते हैं कि कब, किसकी कमजोर नस दबाई जाए और वह कांय-कांय कर उठे। ऐसे लोगों के लिए यह मानसिक सुख और सुकून पाने का अवसर होता है। बहरहाल, इस मामले में बस इतना समझ लो कि अभ्रक की चमक साहब की किस्मत तक नहीं पहुंच रही। मौजूदा संसार में सारी सफलता-असफलता को लाभ से जोड़कर ही देखा जाता है। गुरु की बातों ने विराम लिया। काम पूरा हो चुका था। हमने भी हाथ जोड़े और निकल पड़े अपने रास्ते।

तीखी तपिश : 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा डाल्टनगंज का पारा

प्रचंड गर्मी व हीटवेव के असर ने  
जन-जीवन को किया अस्त-व्यस्त

40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा 5 जिलों का अधिकतम तापमान

**PHOTON NEWS RANCHI :** पिछले कुछ दिनों से झारखंड में प्रचंड गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों तक मुश्किलें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई जिले हीटवेव की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल पलामू के डाल्टनगंज का है। पिछले 24 घंटे में यहां का पारा 44.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। यहां 48 घंटे पूर्व अधिकतम पारा 45.2 डिग्री तक पहुंच गया था। शनिवार को यहां अधिकतम 44.8 और न्यूनतम 22.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची में भी हाल बेहाल है। रांची का तापमान 48 घंटे के भीतर

रांची का तापमान 48 घंटे के भीतर 0.3 बढ़कर 39.2 डिग्री तक पहुंचा



आज 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 8 जिलों में रविवार को गर्जन के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं इस दौरान राज्य के तीन जिलों गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव (लू) चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जिन 08 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है उनमें गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं।

0.3 डिग्री बढ़कर 39.2 डिग्री तक पहुंच गया है। रांची के नामकुम और

लू को लेकर हेमंत सख्त, अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश

भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित पंचायत प्रतिनिधियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने जगहों को सर्वोपरि बताते हुए साफ किया है कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करे, ताकि राज्य के किसी भी नागरिक को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों (एसपी), थाना प्रभारियों, अत्याधिकारियों (सीओ), प्रखंड विकास पदाधिकारियों (वीडीओ) और पंचायत प्रतिनिधियों को कड़ा निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर आम जनता और राहगीरों के लिए पेयजल (पीने के पानी) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि पानी की व्यवस्था वाली जगहों पर सख्त सुचना (साइनबोर्ड) भी प्रदर्शित की जाए, ताकि राहगीरों को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके और उन्हें भीषण गर्मी में राहत मिले। गहराते जल संकट पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को सीधी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आदेश दिया है कि जहां कहीं भी पानी की किल्लत या संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां बिना किसी देरी के तत्काल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।



पिछले 9 दिनों में तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी

पेट्रोल प्रति लीटर 87 व डीजल 91 पैसे और महंगा, नई दरें लागू

NEW DELHI @ PTI :

देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 92.49 रुपये पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतें ₹1 प्रति किलो बढ़ गई हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81.09 रुपये प्रति किलो मिलेगी। पिछले 9 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले



सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपये और फिर 18 मई को एक रुपया बढ़ाया था। नई कीमतें 23 मई से लागू हो गई हैं। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्सेर 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था।

केंद्र सरकार के कई विभागों में 51 हजार से अधिक युवाओं को मिली नौकरी नई अर्थव्यवस्था व टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : पीएम

NEW DELHI @ PTI :

शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 हजार से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए जांब लेटर सौंपे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश का युवा विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला है। आने वाले वर्षों में नई अर्थव्यवस्था तथा टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में

देश की विकास यात्रा के जिम्मेदार भागीदार बनेंगे युवा



**रांची-धनबाद में 432 उम्मीदवारों को मिले नियुक्ति पत्र**  
**RANCHI :** केंद्र सरकार की ओर से रांची और धनबाद में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देशभर के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित हुआ। रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस स्थित साभागार में आयोजित रोजगार मेला में 132 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे।

रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देशभर के हजारों युवाओं और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नियुक्ति पाने वाले

युवा रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं तथा वे देश की विकास यात्रा के जिम्मेदार भागीदार बनेंगे।

झारखंड के 36 आईएसएस अफसरों का हुआ तबादला तीन जिलों के बदले डीसी

PHOTON NEWS RANCHI :

शनिवार को हेमंत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के 36 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत तीन जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग छवि रंजन को खेल निदेशक, बनाया गया है। साथ ही उन्हें कार्यकारी निदेशक, खेल प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अभियोजन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शांशि प्रकाश झा को प्रबंध निदेशक, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रतीक्षारत जीशान कमर को विशेष सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बनाया गया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन को प्रशासक, सुवर्ण रेखा परियोजना, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक सुनील कुमार सिंह को विशेष सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग



प्रतीक्षारत जीशान  
कमर बाने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव

पूर्वी सिंहभूम के डीसी  
राजीव रंजन को मिला सुवर्ण रेखा परियोजना का अतिरिक्त प्रभार

विजय कुमार गुप्ता  
बाने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त

बनाया गया है। विशेष सचिव, वित्त विभाग विजय कुमार गुप्ता को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्रतीक्षारत फैज अक अहमद मुमताज को अपर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के 147 अफसरों का भी तबादला किया गया है। **शेष पेज 04 पर**

सौरभ कुमार देवघर व जावेद हुसैन खूंटी डीसी

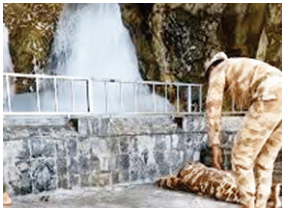
कृषि निदेशक भोर सिंह यादव को अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग में पदस्थापित किया गया है। प्रबंध निदेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम वरुण रंजन को झारखंड एक्स्प्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार को अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बनाया गया है। पशुपति नाथ मिश्रा उपविभागाध्यक्ष आर्युक्त गढ़वा को उपायुक्त गढ़वा बनाया गया है। खूंटी के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानीया को देवघर का नया उपायुक्त बनाया गया है, जबकि पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन को खूंटी का उपायुक्त

नियुक्त किया गया है। वी. श्रीकांत को उप विकास आयुक्त, गोड्डा तथा अनिष रंजन को उप विकास आयुक्त, गुमला बनाया गया है। निदेशक उद्यान के पद पर पदस्थापित माधवी मिश्रा को निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी तथा झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी इन्ोवेशन लेब का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मितल को झारखंड राज्य आजीविका सर्वजन सौसाइटी का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। पर्यटन निदेशक जाधव बिजया नायरण राव को अपर सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में पदस्थापित किया गया है।

सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने सबसे पहले किए दर्शन बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का बना शिवलिंग

AGENCY SRINAGAR :

अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले शनिवार को बर्फ से बने शिवलिंग (बाबा बर्फानी) की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि 6 से 7 फीट का शिवलिंग अपना आकार ले चुका है। इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन भी किए। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुला से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इन दिनों रास्ते में सामान्य जवानों पर 6 से 8 फीट और हिमस्खलन वाले इलाकों में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी है।



बालटाल मार्ग पर 9 किमी और नूनवान-पहलनाम मार्ग पर 8 किमी ट्रैक से बर्फ हटाई जा चुकी है। ट्रैक को 12 फीट चौड़ा करने, सहस्र सुधारने, रिटर्निंग वाल और कल्वर्ट बनाने का काम भी चल रहा है। इस बार बेस कैंप में टेंट की जगह प्री-फैब्रिकेटेड और फाइबर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को आरामदायक और आधुनिक आवास जैसी सुविधा मिल सकेगी।

न्यू मॉडल झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकार से ट्रस्टिज प्लेस पर बनेगी स्थानीय प्रशासन जैसी व्यवस्था

ट्रस्टिज स्पॉट रहेंगे चकाचक, पर्यटकों को भी मिलेगी विशेष सुविधा

PHOTON NEWS RANCHI :

हेमंत सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के संचालन और रख-रखाव के लिए झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकार व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत पर्यटन स्थलों पर स्थानीय प्रशासन की तर्ज पर प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि साफ-सफाई, पार्किंग, अतिक्रमण हटाने और पर्यटक सुविधाओं का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सके। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने 'द फोटोन न्यूज' को बताया कि पर्यटन विभाग और नगर विकास विभाग इस मॉडल पर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत नगरपालिका नियमावली की तर्ज पर



अधिकार तय किए जाएंगे। जिस प्रकार नगर निगम क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक अधिकार

पर्यटन और नगर विकास विभाग समन्वय के साथ बेहतर तरीके से कर रहे काम नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा नया सिस्टम व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि के रूप में विकास

सरकार की योजना है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एक संगठित प्रबंधन तंत्र तैयार किया जाए, जिससे पर्यटन क्षेत्रों में व्यवस्था और अनियंत्रित गतिविधियों पर रोक लग सके। इसके तहत संबंधित प्राधिकार को सफाई शुल्क, पार्किंग शुल्क और अन्य सेवा शुल्क लेने का अधिकार भी दिया जाएगा। इन शुल्कों से प्राप्त राशि का उपयोग पर्यटन स्थलों के रख-रखाव, कचरा प्रबंधन, प्रकाश

प्रदान होते हैं, उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्रों में भी प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अधिकार दिए जाएंगे, ताकि वे अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई कर सकें। नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

सकेगे। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यटन को केवल दर्शनीय स्थल तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी सोच के तहत पर्यटन स्थलों पर स्थायी प्रबंधन व्यवस्था, स्थानीय रोजगार और बेहतर पर्यटक सुविधाओं को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है।

प्रस्ताव को कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी

पर्यटन विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद अब विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों का चिह्निकीकरण, प्रबंधन ढांचा तैयार करने और संबंधित निकायों को अधिकार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से इस प्राधिकार व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इनमें प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जलप्रपात क्षेत्र, धार्मिक, धार्मिक स्थल और इंको-टूरिज्म केंद्र शामिल किए जाएंगे।

पार्किंग व्यवस्था विकसित करना और पर्यटक सुविधाओं का नियमित संचालन शामिल होगा।





# युमथांग वैली : बादल, बर्फ और फूल

दिल्ली की सर्दियों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। धुंध से ढंकी सुबहें, मेट्रो की भीड़, ट्रैफिक का शोर और समय से आगे निकल जाने की होड़ के बीच मन बार-बार किसी ऐसी जगह की तलाश करता है, जहां प्रकृति अब भी अपनी धीमी लय में सांस ले रही हो। शायद इसी तलाश ने मुझे सिक्किम की युमथांग वैली की ओर खींच लिया। वर्षों से सुनता आया था कि पूर्वी हिमालय की यह घाटी हर मौसम में अपना रंग बदलती है- कभी फूलों से भरी, कभी बादलों में खोई और कभी बर्फ की सफेद चादर में ढंकी हुई। दिल्ली से मेरी यात्रा शुरू हुई। सुबह की उड़ान से मैं बागडोगरा पहुंचा। विमान से उतरते ही हवा बदल चुकी थी। यहां ठंड में नमी थी और हवा में पहाड़ों की हल्की खुशबू घुली हुई थी। एयरपोर्ट के बाहर टैक्सियों की कतार लगी थी और हर गाड़ी की विंडशील्ड पर रंगीन प्रेयर प्लैग्स हवा में लहरा रहे थे। मुझे गंगटोक पहुंचना था। जैसे-जैसे सड़क मैदानों से पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी, वैसे-वैसे दृश्य बदलते गए। कुछ ही देर में तीस्ता नदी हमारे साथ बहने लगी। पहाड़ों के बीच हरे रंग की यह नदी पूरे रास्ते सफर की साथी बनी रही। कहीं उसका बहाव शांत दिखाई देता, तो कहीं वह चट्टानों से टकराकर तेज आवाज के साथ आगे बढ़ती। रास्ते में छोटे ढाबे, बादलों में खोते गांव और पहाड़ी मोड़ों पर बने बौद्ध स्तूप सफर को किसी चलचित्र जैसा बना रहे थे।

गंगटोक पहुंचते-पहुंचते शाम हो चुकी थी। पहाड़ों पर बसी रोशनियां दूर से किसी तारों भरे आकाश जैसी दिखाई दे रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन शहर की रफ्तार दिल्ली की तुलना में कहीं धीमी और सुकून भरी लगी। होटल की बालकनी से दूर पहाड़ों पर तेरते बादलों को देखते हुए महसूस हुआ कि हिमालय केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अगली सुबह मेरी यात्रा युमथांग वैली की ओर शुरू हुई। गंगटोक

## युमवकड़ की पाती

रहा था, तो कहीं धुंध के बीच सफेद रेखा की तरह दूर चमक रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ मौसम भी बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई थी। रास्ते में छोटे-छोटे गांव दिखाई देते, जहां लकड़ी के घरों की छतों पर रंगीन प्रेयर प्लैग्स लहरा रहे थे। पहाड़ों में जीवन कठिन जरूर है, लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर एक सहज शांति दिखाई देती है।



की चादर में बदल जाती है। शायद यही कारण है कि इसे 'वैली ऑफ फ्लावर्स' कहा जाता है। मैं काफी देर तक घाटी में बिना कुछ बोले चलता रहा। हवा में ऐसी ठंडक थी, जो चेहरे को छूते ही भीतर तक उतर जाती थी। लेकिन उस ठंड के बीच भी एक गहरी शांति थी। यहां आकर महसूस होता है कि प्रकृति इंसान को विनम्र बना देती है। हमारी रोजमर्रा की चिंताएं इन विशाल पहाड़ों के सामने निकलते समय पूरा रास्ता बादलों और बर्फ के बीच से गुजर रहा था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और दूर चोटियां सुनहरी दिखाई देने लगी थीं। रास्ते में याक चरते दिखाई दिए और कई जगह पहाड़ों पर जमी बर्फ अब भी चमक रही थी। फिर अचानक एक मोड़ के बाद युमथांग वैली सामने थी।

इलाका चीन सीमा के करीब है। ज़ीरो प्वाइंट पहुंचते ही चारों ओर केवल सफेद बर्फ फैली दिखाई दी। तेज हवा चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन उस ठंड के बीच भी लोग उत्साह से भरे हुए थे। कुछ बच्चे बर्फ से खेल रहे थे, तो कुछ पर्यटक खामोश खड़े पहाड़ों को निहार रहे थे। वहां खड़े होकर एहसास हुआ कि हिमालय की असली शक्ति उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी शांति में छिपी है। वापसी के दौरान एक छोटे ढाबे पर रुककर मैंने गरम थुकपा और मोमो खाए। बाहर बफ़ीली हवा चल रही थी और भीतर लकड़ी के चूल्हे की गर्माहट थी। पहाड़ों में साधारण भोजन भी किसी विशेष अनुभव जैसा लगता है। जब मैं वापस गंगटोक लौट रहा था, तब रास्ते भर मन बार-बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था। पहाड़ धीरे-धीरे दूर होते जा रहे थे, लेकिन भीतर युमथांग की शांति अब भी बाकी थी। शायद यही इस घाटी का सबसे बड़ा आकर्षण है- आप यहां कुछ दिनों के लिए आते हैं, लेकिन इसकी नीरवता लंबे समय तक आपके भीतर ठहर जाती है।



**संजय शेफर्ड**  
नई दिल्ली



SCAN ME

1. हमें अपना फीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।  
2. आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

से लाचुंग तक का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन हर मोड़ पर हिमालय अपना नया रूप दिखाता है। सड़कें कभी गहरी घाटियों के किनारे से गुजरतीं, तो कभी

घने जंगलों के भीतर खो जातीं। रास्ते में कई झरने दिखाई देते रहे। कहीं पानी चट्टानों से सीधा सड़क के पास गिर रहा था, तो कहीं धुंध के बीच सफेद रेखा की तरह दूर चमक रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ मौसम भी बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई थी। रास्ते में छोटे-छोटे गांव दिखाई देते, जहां लकड़ी के घरों की छतों पर रंगीन प्रेयर प्लैग्स लहरा रहे थे। पहाड़ों में जीवन कठिन जरूर है, लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर एक सहज शांति दिखाई देती है।

शाम तक मैं लाचुंग पहुंचा। लगभग नौ हजार फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा गांव किसी चित्र जैसा सुंदर लगता है। चारों ओर बर्फ से ढंकी चोटियां, बीच से बहती नदी और लकड़ी के पारंपरिक घर- सब कुछ इतना शांत था कि समय मानो धीमा पड़ गया हो। रात के समय जब आसमान साफ हुआ, तब

अनगिनत तारे दिखाई देने लगे। शहरों में शायद हम यह भूल चुके हैं कि रात का आसमान वास्तव में कितना विशाल होता है। अगली सुबह युमथांग वैली की ओर निकलते समय पूरा रास्ता बादलों और बर्फ के बीच से गुजर रहा था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और दूर चोटियां सुनहरी दिखाई देने लगी थीं। रास्ते में याक चरते दिखाई दिए और कई जगह पहाड़ों पर जमी बर्फ अब भी चमक रही थी। फिर अचानक एक मोड़ के बाद युमथांग वैली सामने थी।

पहली नजर में ऐसा लगा मानो किसी चित्रकार ने पूरी घाटी को रंगों से भर दिया हो। चारों ओर फैले घास के मैदान, पीछे बर्फ से ढंकी चोटियां और बीच से बहती नदी- यह दृश्य शब्दों से कहीं अधिक सुंदर था। वसंत के मौसम में यहां हजारों रंग-बिरंगे रोडोडेंड्रोन फूल खिलते हैं, जबकि सर्दियों में पूरी घाटी सफेद बर्फ

## व्यंग्य ■ बर्बरीक

आजकल एआई से रचनाएं लिखवाकर तमाम विद्वान और विदुषी, कवि और शायर बने बैठे हैं। एआई से लिखी रचनाओं पर अक्सर इल्जाम आया होता है कि इन रचनाओं में मौलिकता नहीं होती। पर साहित्यिक चोरी/टीप, थीम उड़ाने या हू-ब-हू नकल करने की परंपरा हिंदी साहित्य और उर्दू अदब में काफी पुरानी है। लोगबाग बताते हैं कि अजीम शायर फिराक गोरखपुरी साहब एक मुशायरे में शिरकत कर रहे थे। अब जहां फिराक जैसे अदबी सूरज रौशन हो वहां किसी और की कोई ना तो बात कर रहा था और ना ही तवज्जो दे रहा था। तभी एक नौजवान शायर ने तवज्जो पाने और महफिल में अपना रंग उमाने की नीयत से अपनी रचना पढ़ने के बजाय फिराक साहब की ही रचना पढ़ दी। जलसा फारिग होने के बाद फिराक साहब ने उस शायर को बुलाया और कहा- 'गजब करते हो मियां, तुमने मेरा ही कलाम अपने नाम से पढ़ दिया और मेरे ही सामने'। शर्मिंदा होने के बजाय उस शायर ने अपनी साहित्यिक चोरी को उर्रुज पर ले जाते हुए कहा 'फिराक साहब, कभी -कभी ख्याल से ख्याल टकरा जाते हैं'। फिराक साहब उस्ताद जो ठहरे। उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में जवाब दिया 'ऐसा है मियां, साइकिल से साइकिल तो टकरा सकती है। मगर साइकिल कहीं हवाई जहाज से थोड़े ना टकरा सकती है'। यह कहते हुए फिराक साहब ने अपने और उस शायर के ख्यालात के मेयार का फर्क बतावा दिया। उस पर तुरां यह कि वह नज्म चोर शायर शर्मिंदा होने के बजाय वेशर्मा से फिराक साहब के सामने हंस्ता रहा।

आजकल तो कवि सम्मेलनों में घड़ल्ले से दूसरे की रचनाएं पढ़ने वालों की तादाद पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हो गई है। पहले ऐसे रचनाचोर पुरानी और अल्पज्ञात किताबों से काम निकाला करते थे। मगर फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि आ जाने के बाद उनके लिए टीपना काफी आसान हो गया है। सोशल मीडिया से टीपी हुई रचनाएं ऐसे लोग साहित्यिक आयोगजों में अपने नाम से पढ़ते हैं। वहां कोई आपत्ति नहीं करता तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती है और थोड़ा बहुत हेर-फेर करके कुछ दिन बाद अपने निजी कविता संग्रह में या अपने नाम से साझा संकलन में प्रकाशित करा लेते हैं। महानगरों से दूर बैठे किसी अल्पज्ञात शहर या गुमनाम गांव में बैठे किसी रचनाकार को यह पता ही नहीं चल पाता कि उसका चिराग कहीं और रोशनी लुटा रहा है या यूं कहें कि उसके चिराग की रोशनी लुट ली गई है।

फेसबुक से चुरा कर इंस्टाग्राम पर कविता पोस्ट करने वालों की भी तादाद



काफ़ी बड़ी है। क्योंकि ये थोड़ी सेफ साहित्यिक चोरी मानी जाती है। क्योंकि ज्यादातर अच्छे रचनाकार फेसबुक पर ही सक्रिय हैं और इंस्टाग्राम पर सक्रिय नहीं हैं। इसमें एक और बात यह है कि इंस्टाग्राम पर उस व्यक्ति को पूरी पोस्ट दिखती नहीं जो इंस्टाग्राम पर नहीं है। तो इस तरह से किसी रचनाचोर का फेसबुक से चुरा कर इंस्टाग्राम पर अपने नाम से पोस्ट करना सेफ पार्किंग जैसा है। कुछ समय पहले तो गजब हुआ। बोल्ट विषयक लिखने वाली एक लेखिका को एक मशहूर साहित्यकार की कहानी टीप कर एक नामी मासिक साहित्यिक पत्रिका में अपने नाम से प्रकाशित करा ली। लोगों ने उसकी साहित्यिक चोरी पकड़ ली। उस लेखिका की बहुत आलोचना हुई। काफी शाब्दिक लानत-मलामत के बावजूद वह लेखिका टस से मस नहीं हुई और उल्टे थेयरई पर उतारू होकर लोगों से लड़ने-भिड़ने लगी। पदमशी रामदरश मिश्र जी की कहानी हिमशैल एक लेखक के नाम से एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी पत्रिका के अमले अंक में इस बाबत रामदरश जी का पत्र भी प्रकाशित हुआ था। यह कोई एक घटना नहीं है। ऐसे-ऐसे बाकामाल और ढीठ लोग होते हैं कि जाने-अनजाने में मूल रचनाकार के सामने ही उसकी रचना को अपनी रचना बताकर सुना देते हैं। इस हादसे से बड़े-बड़े रचनाकार रूबरू हो चुके हैं।

ऐसी ही साहित्यिक चोरियों पर उर्दू के अजीम शायर ने एक बार चुटकी लेते हुए कहा था कि झ 'मेरे कारोबार में सबने बड़ी इमदाद की, दाद लोगों की, गला मेरा और गजल उस्ताद की'। उर्दू में दो तरह की चोरी मानी गई है। पहले को सरका और दूसरे को तवारुद

# 'चोरी और सीनाजोरी'



कहते हैं। जब किसी की रचना हूबहू चुरा ली जाए तो उसे सरका और थोड़ा घालमेल के साथ प्रस्तुत की जाय तो उसे तवारुद कहते हैं। ऐसे कवियों को लोग चरबा करने वाला शायर भी कहते हैं। हिंदी सिनेमा के कुछ गीतकार और संगीतकार इसके लिए कुख्यात हैं ही। कोरोना काल में तो एक मीम बड़ा वायरल हुआ था कि कोरोना से निपटने के लिए अपनी बालकनी में थाली बजाते लोग अनु मलिक को देखते ही थाली बजाना बंद कर देते थे कि थाली बजाने की आवाज कहीं अनु मलिक लेकर किसी अगले गीत की धुन तैयार करके अपने नाम से अगली फिल्म में बजावा दें।

तवारुद के उस्ताद तो लोकप्रिय गीतकार गुलजार साहब भी माने जाते रहे हैं। मशहूर लोकगीत 'ता थाईया -ता थाईया' को उन्होंने 'छैयां-छैया' बनाकर पेश किया। उन्होंने फिल्म 'इश्किया' में 'इन्ने -बतूता, पहन के जुता' को पेश किया, जो कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मशहूर कविता 'इन्ने-बतूता' से काफी मिलती थी। इस बात पर विवाद बढ़ा तो लोगों ने इस समानता पर काफी सवाल खड़े किए। बात बढ़ती देख से गुलजार साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि उनका गीत इन्ने बतूता कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से कुछ हद तक मिलता है और उन्होंने सक्सेना साहब की कविता से प्रेरणा लेकर यह गीत लिखा था। यह और बात है कि फिल्म के क्रेडिट में बतौर गीतकार गुलजार साहब का ही नाम था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का कहीं भी जिक्र नहीं था।

ऐसी बात नहीं है कि हिंदी साहित्य में सिर्फ साहित्यिक चोरी/नकल और टीप में ही घोटाला चल रहा है। इसके अलावा डाक्ट्रेट और डाक्टर साहब के नाम पर भी एक अलग ही घोटाला चल रहा है। अमूमन चिकित्सा शास्त्र से स्नातक या पीयचडी किया हुआ व्यक्ति अपने नाम के आगे डाक्टर और उपाधि लिखते हैं। इसके अलावा यदि किसी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो तो ऐसे व्यक्ति को कुछ संस्थान सम्मान स्वरूप मानद डाक्ट्रेट की उपाधि देते हैं। परंतु आजकल तो मंचीय कविता में खूब डाक्टर-डाक्टर खेला जा रहा है। इसमें ना तो चिकित्सा शास्त्र की डिग्री, ना ही पीएचडी और ना ही मानद डाक्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। यहां तो स्वयंभू और स्वघोषित 'डाक्टर साहब' बोले जाने का खेला चल रहा है। मतलब कविवर ने तीस बरस पहले व्यक्तिगत बीए किया था, बेचते हैं खोया (मावा) और शहर से बाहर कभी कविता कहने गए नहीं और ना जाने कब रसिक उतरीलवी से डाक्टर उतरीलवी बन गए। ऐसे हजरात मंचीय कविता के मंचों से कुछ ज्यादा ही तवज्जो और सम्मान पाने के लिए तमाम चोंचले पालते हैं। ऐसे लोग कुछ चेले भी पाल कर रखते हैं जो मंच के नीचे से उन्हें वाह डॉ. साहब-वाह डॉ.साहब की आवाज लगा कर दाद दिया करते हैं। उन्हें बरसों से जानने वाले किसी पुराने और सीनियर कवि ने अगर उनके अचानक प्राप्त हुए डॉक्टरेट के बारे में पूछने की गुस्ताखी कर दी तो उससे बुरी तरह से उलझ जाएंगे

या फिर कोई झूठ गढ़कर सुना देंगे- फलां यूनिवर्सिटी ने मुझे मानद डिग्री प्रदान की है। जबकि ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का कभी कोई वजूद ही नहीं होता। क्योंकि या तो वो संस्थान बंद हो चुका होता है या कभी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। हिंदी-उर्दू कवि सम्मेलन /मुशायरों के मंच पर अनेक कवयित्रियां ऐसी हैं जिनके पास अपना कलाम नहीं है। लिखने का काम उनके उस्ताद या उनके हामी करते हैं। उनका काम महज नाजो अदा से कविता सुनाने का होता है। इनमें से कई तो इतनी शांति हैं कि नवोदित कवयित्री को इसी शर्त पर मंचों पर ले जाती हैं कि लिफाफे और इनाम में जो भी मिलेगा, उसका तीस परसेंट कमीशन में उन्हें देना होगा। बहुतेरी तो हिंदी की काव्य संस्थाएं और उर्दू की मजलिसें चला रही हैं और उसके नाम पर अच्छा खसा अनुदान और चंदा भी वसूल रही हैं। ये सब जानने के बावजूद तमाम 'पुराने चावल' यानी उपद्राज कवि -शायर इन पर कृपा बरसाने को लालायित रहते हैं। धीरे -गंभीर साहित्यकारों की यह जिम्मेदारी है कि साहित्य की सरिता में खर-पतवार की तरह उग आये इन रचनाचोरों को समाज के सामने लाएं और समाज को साहित्यिक प्रदूषण से बचाएं। इस टीप/ चोरी/ नकल से व्यथित और आजिज होकर झल्लाते हुए एक शायर ने कहा था- 'शायरी चारा समझकर कुछ गधे चरने लगे, शायरी आये नहीं, शायरी करने लगे'।

## कविता



पियंका कुमारी  
जमशेदपुर

## ये बारिश की बूंदें

छम छमा छम करती गिरतीं ये बारिश की बूंदें,  
झम झमा झम मनवा नाचे देखे बारिश की बूंदें।  
कहीं दहलाये कहीं बहलाये ये बारिश की बूंदें,  
छम छमा छम करती गिरतीं ये बारिश की बूंदें।।

प्रियतम की याद दिलातीं भरमातीं हैं मन को,  
राग रागिनी बन छनकातीं हैं ये मेरे तन को।  
अगन लगातीं लगन जगातीं ये बारिश की बूंदें,  
छम छमा छम करती गिरतीं ये बारिश की बूंदें।।

सूखी हुई डाली को रंग दें, रंग दें अपने रंग में,  
प्यास बुझातीं हैं हर मन की भरतीं अपने अंग में।  
बन कर हरियाली छा जातीं ये बारिश की बूंदें,  
छम छमा छम करती गिरतीं ये बारिश की बूंदें।।

मंद-मंद मुस्कता तुंग बैठ बरखा के घर में,  
देख नजारा भर लेतीं हूँ मैं भी अपने उर में,  
है प्रेम की मीठी सी एहसास ये बारिश की बूंदें,  
छम छमा छम करती गिरतीं ये बारिश की बूंदें।।









**पर जार**

मगध जेल में संघालित आधारभूत समिति को लेकर शनिवार को वीथी पर यूटिलिटी टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण सदस्यता रामगढ़ के उपायुक्त चतुराज ने खींची। परियोजनाओं की अवहन स्थिति की जानकारी बागमो एवं परियोजना अधिकारियों को त क करने का निर्देश दिया। शेटक के दौरान की विभिन्न संघालित परियोजनाओं, पथ निर्माण लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग सहित गमगम संघालित, कास्टाई प्रोग्राम रिपोर्ट (एफआरए), एनओसी, भूमि का अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े डाटा, ई। उपकरणों ने स्पष्ट कहा कि विकास कंरी डीरिया कर नहीं की जाएगी।

पञ्चांगवैद्य के आलायक प्रमाण प्रदिया गया है। प्रतीक्षातर प्रेषणा दीक्षित को ग्रामीण विकास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। देवघर के उपमुख्य शिक्षा प्रकाश सिंह को अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग गृह कार्यपालक निदेशक, झारखंड राज्य आरोग्य समिति एवं परियोजना निदेशक, झारखंड एस नयनंजना सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रतीक्षातर कुमार ताराचंद को अपर सचिव, जल ससाबन विभाग तथा कृषि श्री जी को अपर सचिव, गृह विभाग बनाया गया है। समीरा एस को संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा विदेश कुमार यादव को संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग में पदस्थानित किया गया है। झारखंड प्रशासनिक प्रकाश 66 अफसर श्री जी तबाला किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग में अधिसूचना जारी कर दी है।







## बंगाल में जंगलराज का खाल्मा

जब भी जंगलराज का उल्लेख होता है तो उस दौर के बिहार का स्मरण हो आता है, जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय बिहार अराजकता को लेकर इस कदर बदनाम हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को उसके पुष्परिणाम आज तक भोगने पड़ रहे हैं। चुनावों के समय राजद के विरोधी दल लोगों को लालू के जंगलराज के भयावह दिनों की याद दिलाते हैं और इतने से ही उनका काम आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि बिहार के लोग यह भूल नहीं सके हैं कि लालू यादव के शासनकाल में किस तरह अपहरण और फिरोती ने उद्योग का रूप ले लिया था और राज्य के अनेक शहरों में भी सांझ ढलते ही कैसा सन्नाटा छा जाता था। बिहार के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि शहाबुद्दीन सरीखे माफिया का कैसा आतंक था और उनके जैसे बाहुबलियों को किस प्रकार लालू का संरक्षण प्राप्त था। जैसे यह पता नहीं कि बिहार राजद के जंगलराज की यादों से कब मुक्त होगा, वैसे ही यह कहना भी कठिन है कि पश्चिम बंगाल ममलत बनगों के कुशासन की पराकाष्ठा को कब तक भूल सकेगा। यह कुशासन एक किस्म का जंगलराज ही था और कुछ मायनों में तो बिहार से भी बदतर था। लालू यादव का शासन इसलिए जंगलराज के रूप में कुख्यात हुआ, क्योंकि अगस्त 1997 में किसी मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी थी, बिहार में कोई सरकार नहीं है, यह जंगलराज से भी खराब है। ऐसी कोई टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता शासन को लेकर तो नहीं की, पर हिंसा और भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर उसने उसे न जाने कितनी बार फटकार लगाई, जैह चाहे 2021 की चुनाव बाद की हिंसा रही हो या आरजी कर अस्पताल कांड या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला। अभी हाल में ममता सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन न देने के लिए फटकार लगी। ममता सरकार को कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार फटकार लगी। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा के चलते जो लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे, उनमें से कुछ तो महीनों तक अपने घरों को लौट नहीं सके थे। यह हिंसा इतनी खुली और भीषण थी कि यदि नेहरू और इंदिरा का जमाना होता तो शायद ममता के शपथग्रहण के पहले ही राष्ट्रपति शासन लग जाता। न्यायपालिका के आदेश पर इस भीषण हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी, क्योंकि जब यह हिंसा हो रही थी तो पुलिस मुकदशक बनी हुई थी। इस आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासको का कानून लागू है। अराजकता के मामले में संदिग्धवाली की हिंसा को भी नहीं भूला जा सकता। चूँकि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार नेता को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उसे बहुत दिनों बाद गिरफ्तार किया जा सका। अराजकता को बयान करने वाली मुर्शिदाबाद की घटना को भी नहीं भूला जा सकता। वक्फ कानून के कथित विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जमकर नंगा नाच किया गया। तब उपद्रवी तत्वों के आतंक से डरे हुए लोगों ने असम और झारखंड जाकर अपनी जान बचाई थी। ममता के शासन के समय टीएमसी के बाहुबली नेताओं-कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा संरक्षित गुंडों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा हुआ था कि वे पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को भी निशाना बनाने में संकोच नहीं करते थे। वे हर किसी से अवैध वसूली, उगाही करते थे। ममता में यह कट मनी यानी कमीशनखोरी और तोलाबाजी यानी अवैध वसूली के रूप में कुख्यात थी। बंगाल से गुजरने वाला कोई मालवाहक वाहन अवैध वसूली से बच नहीं पाता था। इसी तरह दो-चार सौ रुपये रोज कमाने वाले फुटपाथ दुकानदार भी हफ्ता वसूली के शिकार थे। लोग टीएमसी नेताओं को पैसे दिए बिना न तो जमीन खरीद सकते थे और न ही घर बनवाने के लिए सामग्री। इस सबसे ममता अनजान नहीं थीं और इसका प्रमाण यह है कि 2019 में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी पार्टी में चोर नहीं चाहिए और जिन्होंने भी कट मनी वसूली है, उसे वे वापस करें। जाहिर है किसी ने ऐसा नहीं किया। उल्टे बाद में यह सुनने को मिला कि ममता ने जो कहा, उसका गलत मतलब निकाला गया। ममता के 15 वर्षों के शासन में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटीं, जिनसे राज्य सरकार की बदनामी हुई, लेकिन इस सबके बाद भी उनके कुशासन को कभी जंगलराज की संज्ञा नहीं मिली। इसका कारण यह रहा कि दिल्ली और कोलकाता के मीडिया का एक हिस्सा उन्हें सदैव फाइटर की संज्ञा देता रहा और बड़ी सेक्युलर नेता के तौर पर रेखांकित करता रहा। चूँकि ममता सेक्युलर नेता मानी जाती थीं, इसलिए लिबरल किस्म के लोगों ने यह देखने की चेष्टा ही नहीं की कि वे किस तरह अल्पसंख्यकों और यहां तक कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के तुष्टीकरण में लिप्त हैं और उन्होंने अपने कैडर को किस प्रकार मनमानी करने की छूट दे रखी है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद उत्साहित, भावुक और ममता के शासनकाल में प्रताड़ित अथवा पलायन करने को मजबूर हुए लोगों की जैसी खबरें, फोटो, वीडियो आ रहे हैं, वे चीख-चीख कर यही कह रहे हैं कि ममता का शासन निरंकुशता का खौफनाक पर्याय बनकर रह गया था।

## Social Media Corner

सब के हक में...

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नदीन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में, उन्होंने संघटन को मजबूत करने और हमारे कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी नवमेसी सोच, ऊर्जावान नेतृत्व और संगठनात्मक कार्य एवं प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें सर्वत्र सम्मान दिलाया है। उनका कार्य सेवा और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के दशनांत है। राष्ट्र की सेवा में उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, सीओ, वीडीओ, विचारत प्रतिनिधियों एवं सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने कार्यालयों के बाहर, एवं सार्वजनिक स्थलों पर आम जनो के लिए पेमेजल की सुगन्धित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा इसकी स्पष्ट सूचना भी प्रदर्शित करें, ताकि राहगीरों एवं आम लोगों को राहत मिल सके। साथ ही सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि जहाँ कहीं भी जल संकट की स्थिति हो, वहाँ तत्काल टैकरो के माध्यम से जलपूति, चापाकलों की मरम्मत एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। किसी भी गाँव, टोला या मोहल्ले में पेमेजल की कमी के कारण लोगों को परेशानी न हो – यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भीषण गर्मी के इस दौर में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करे। जनहित सर्वोपरि है।

(मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

## उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में भी सबका साथ-सबका विकास



सियाराम पांडेय 'शांत'

राजनीति की सामान्य समझ रखने वालों की मानें तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में छह नए मंत्रियों के जरिए जहां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की गई है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को साधने के प्रयास भी हुए हैं। भाजपा ने सर्व समाज को यह संदेश देने की पुरजोर कोशिश की है कि सबका साथ, सबका विकास उसके लिए महज सियासी नारा नहीं बल्कि अपनी कार्यशैली और रीति-नीति में भी इसका बखूबी ख्याल रखती है। इस लिहाज से भी इस विस्तार को हल्के में लेना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद के विस्तार से जातिगत जनगणना का राग अलावा रही समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से एक तरह से जमीन खिसका दी है। सपा के बागी विधायक व पूर्व मंत्री मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाकर जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज को भाजपा से जोड़ने का जतन किया है, वहीं भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाकर यह बताते और जताने का प्रयास भी हुआ है कि भाजपा अपने पुराने चावलों की उपेक्षा नहीं करती। अन्य दल से अपने साथ आए साथियों की अनदेखी का तो सवाल ही नहीं। भूपेंद्र चौधरी राज्य के समाज कल्याण मंत्री रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में सरकार गठन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहना दिया है। इस विस्तार के साथ उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। वर्ष 2024 में अगर जितन प्रसाद और अनूप प्रधान सांसद न चुने गए होते तो आज यह संख्या 62 होती। हालांकि योगी कैबिनेट में 60 से अधिक मंत्री रखने की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद का दबाव मुख्यमंत्री पर पहले से ही था, लेकिन उसे मूर्त रूप 10 मई को मिल सका है। दर आयद-दुरुस्त आयद वाली कहावत इस मंत्रिपरिषद विस्तार में बखूबी चरितार्थ हुई है। कुछ लोग इसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देख रहे हैं। राजनीति की सामान्य समझ रखने वालों की मानें तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में छह नए मंत्रियों के जरिए जहां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की गई है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को साधने के प्रयास भी हुए हैं। भाजपा ने सर्व समाज को यह संदेश देने की पुरजोर कोशिश की है कि सबका साथ, सबका विकास उसके लिए महज सियासी नारा नहीं बल्कि अपनी कार्यशैली और रीति-नीति में भी इसका बखूबी ख्याल रखती है। इस लिहाज से भी इस विस्तार को हल्के में लेना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद के विस्तार से जातिगत जनगणना का राग अलाप रही समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से एक तरह से जमीन खिसका दी है। सपा के बागी विधायक व पूर्व मंत्री मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाकर जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज को भाजपा से जोड़ने का जतन किया है, वहीं भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाकर यह बताते और जताने का प्रयास भी हुआ है कि भाजपा अपने पुराने चावलों की उपेक्षा नहीं करती। अन्य दल से अपने साथ आए साथियों की अनदेखी का तो सवाल ही नहीं। भूपेंद्र चौधरी राज्य के समाज कल्याण मंत्री रहे हैं।



पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बल मिलना स्वाभाविक है। भूपेंद्र चौधरी जहां जाट समुदाय में भाजपा के बड़े चेहरे हैं, वहीं पंचायती राज मंत्री के रूप में उनके काम की गूँज प्रदेश के गांव-गांव में है। यह और बात है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था और अब जब पंकज चौधरी के रूप में भाजपा को उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है तो फिर भूपेंद्र चौधरी की योगी मंत्रिमंडल में तीसरी बार ताजपोशी तो बनती ही थी। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। अजीत पाल को पाल-गढ़ेरिया समाज के बीच अच्छी पकड़ है। जाहिर है कि इसका फायदा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। बसराज को विश्वकर्मा की वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में अच्छी पकड़ है। वे पिछड़ी जाति से आते हैं। कन्नौज जिले के तिर्वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश राजपूत का अपने लोधी समाज पर राजनीतिक प्रभाव है। चार बार की विधायक रही कुष्णा पासवान को राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। ऐसे में जो राजनीतिक दल भाजपा को दलित समाज से उनका ताल्लुक़ात है। ऐसे में

के इस निर्णय से उन्हें भी जोर का राजनीतिक झटका लगा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति किए गए सरकार के काम और उनके बीच की एक महिला को मंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें जो गौरव की अनुभूति हुई होगी, वह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। राज्यमंत्री बनाई गई पूजा पाल किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। बसपा से अपना राजनीतिक करियर आरंभ करने वाली पूजा पाल सपा में भी विधायक रही हैं। और अब भाजपा के साथ हैं। अपने पति राजू पाल की हत्या के बाद वे सुखियों में आई थीं। अलीगढ़ के खेर से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। उनकी अपनी फैन फालोइंग है। मतलब मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरने के लिए जरबर्दस्त क्रॉच व्यूह बना दिया है। उसने मंत्रियों के चयन में अनुभव को तो वरीयता दी ही, सामाजिक संतुलन की आधारभूमि भी तलाशी है, यह अपने आप में सुखद संदेश है। कहना न होगा कि योगी-2 सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 5 मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। इस विस्तार में चार मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, इनमें सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ आए सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान,

## संत मुक्ताबाई : सामाजिक-आध्यात्मिक योगदान

महाराष्ट्र की संत परंपरा में संत मुक्ताबाई का नाम अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन ही नहीं थीं, बल्कि स्वयं एक उच्चकोटि की संत, दार्शनिक चिंतक और कवयित्री थीं। वारकरी संप्रदाय में मुक्ताबाई को स्त्री-संत परंपरा की अग्रिम पंक्ति में स्थान प्राप्त है। उनकी वाणी में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, समता और आत्मबोध का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मध्यकाल में जब दुनिया भर के अन्यान्य देशों में महिलाओं को उचित स्थान नहीं था तब भारतीय समाज में मुक्ताबाई ने अपने चिंतन और आध्यात्मिक योगदान से विशेष स्थान अर्जित किया। संत मुक्ताबाई का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के आपेगांव आलंदी क्षेत्र में माना जाता है। वे अपने तीन संत भाई निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव की छोटी बहन थीं। उनका परिवार सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक रूढ़ियों की प्रताड़ना का शिकार हुआ था। उनके पिता विठ्ठलपंत ने पहले संन्यास

लिया था, लेकिन किसी कारण से बाद में फिर से गृहस्थ जीवन में लौटने के कारण समाज ने इनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। इस सामाजिक पीड़ा ने मुक्ताबाई के मन में विद्वेष की जगह करुणा, समता और आध्यात्मिकता को मजबूती से विकसित किया। मुक्ताबाई को आध्यात्मिक संस्कार उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ से मिले थे, जो नाथ संप्रदाय के संत थे। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। मुक्ताबाई की साधना में नाथपंथ की परंपरा और वारकरी संप्रदाय की भक्तिधारा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। वे ईश्वर को बाहरी कर्मकांड में नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता और आत्मबोध में खोजती हैं। दूसरी ओर वारकरी संप्रदाय की विठ्ठल भक्ति और नामस्मरण की परंपरा ने उनकी साधना और अभिव्यक्ति को लोकाभिमुख बनाया। इस प्रकार मुक्ताबाई के व्यक्तित्व में नाथ संप्रदाय और वारकरी भक्ति परंपरा का अद्भुत समन्वय मिलता है।

मुक्ताबाई का जीवन यह प्रतिपादित करता है कि ईश्वर-प्राप्ति, ज्ञान और मोक्ष में स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है। उनकी भूमिका से स्पष्ट हुआ कि स्त्री भी गुरु हो सकती है। स्त्री भी दार्शनिक संवाद कर सकती है। स्त्री भी समाज को दिशा दिखा सकती है। मुक्ताबाई का जीवन वृत्त संत साहित्य, लोककथाओं और परंपरागत आख्यानों पर आधारित है। उनका प्रभाव वारकरी संप्रदाय और मराठी संत साहित्य पर गहरा पड़ा है। उनकी रचनाओं में स्त्री अनुभव, सामाजिक पीड़ा और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अद्भुत समन्वय मिलता है। मुक्ताबाई केवल संत ज्ञानेश्वर की बहन ही नहीं थीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा की सहयात्री भी थीं। अनेक कथाओं में ये उल्लेख भी मिलता है कि जब ज्ञानेश्वर सामाजिक विरोध और मानसिक वेदना से व्यथित होते, तब मुक्ताबाई उन्हें धैर्य, समता और क्षमा का भाव धारण करने का संदेश देती थीं। उनकी प्रसिद्ध उक्ति विश्व योगे ज्ञाले वन्ही, संत सुखे व्हावे पाणी अर्थात जब संसार क्रोध और द्वेष

सच्ची महानता प्रत्येक प्राणियों के प्रति दया और करुणा में होती है। आपण जैसे व्हावे। अवधे अनुमानावे स्वयं जैसे बनो। वैसे ही सबको समझो। मनुष्य स्वयं जैसा होता है वैसा ही दूसरों से अपेक्षा कर सकता है। क्रोधे यावे कोटे। अवधे आपण निधोटे। क्रोधे किस पर करें। सब अपने ही स्वरूप हैं ॥ राग और द्वेष व्यर्थ हैं, क्योंकि सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। जीव दातानी चाविली। क्रोणी बत्तीशी तोडिंदली। यदि दांतों ने जीभ काट ली तो क्या कोई अपनी पूरि बत्तीसी तोड देता है। जैसे दांत गलती से जीभ काट लें तो हम दांत नहीं तोड़ते, वैसे ही सब मनुष्य अपने ही है इसलिए उनकी भूलों को क्षमा करना चाहिए। चणे खावे लोखंडाचे। मग ब्रह्मदी नेाचे । लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तब ब्रह्म पद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक साधना से ब्रह्म तत्व को पाना कठिन होता है उसके लिए धैर्य, सहनशीलता और कठोर तप आवश्यक है। संत मुक्ताबाई के ताटी के अभंग वारकरी संत साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध और आध्यात्मिक दृष्टि

से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुक्ताबाई की रचनाएं मुख्यतः अभंग शैली में उपलब्ध हैं। उनकी वाणी सरल, मार्मिक और अनुभवप्रधान है। उनके अभंगों के प्रमुख विषयवस्तु, समता, और सामाजिक भेदभाव का विरोध, वैराग्य- माया, अहंकार और लोभ से मुक्ति का संदेश तथा भक्ति, ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम और समर्पण रहे हैं। मुक्ताबाई का व्यक्तित्व मध्यकालीन समाज में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल गृहस्थी तब सीमित नहीं, बल्कि वह ज्ञान, साधना और समाज सुधार की वाहक भी हो सकती है। उनकी वाणी में स्त्री की स्वतंत्र चेतना, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक अधिकार स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए आधुनिक महिला विमर्श की दृष्टि से मुक्ताबाई का अध्ययन जरूरी है। मुक्ताबाई की विशेषता उनके ज्ञानप्रधान भक्ति दर्शन में दिखाई देती है। जैसे मीराबाई का केन्द्र कृष्णप्रेम है, वैसे ही मुक्ताबाई का केन्द्र आत्मज्ञान और समरसता है।

## दयनीय स्थिति में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले दहाई महीनों में तेजी से घटकर लगभग 550 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह स्थिति कष्ट सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए चिंता का विषय है। विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। इसी के सहारे आयात, अंतरराष्ट्रीय भुगतान और मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखने में होता है। इसका असर आयात और निर्यात दोनों पर पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच जब युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में वैश्विक बाजार में अस्थिरता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर की मजबूती के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट भारत की अर्थ व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का संकेत है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85 फीसद हिस्से का आयात करता है। खाद भी बड़े पैमाने पर भारत को आयात करनी होती है। पेट्रोलियम, खाद और गैस के आयात में भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी सरकार और रिजर्व बैंक को वैकल्पिक उपायों पर विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉलर बॉन्ड जारी करने की योजना सामने आई है। विदेशों में बसे भारतीयों (एनआरआई) को

बांड बेचकर सरकार डॉलर का भंडार बढ़ाना चाहती है। यह योजना सरकार और रिजर्व बैंक के लिए अल्पकालिक राहत देने वाली होगी। एनआरआई निवेशकों से डॉलर प्राप्त कर सरकार विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने का प्रयास करेगी। इससे तत्काल डॉलर की उपलब्धता बढ़ सकती है। रुपये पर पड़ रहा दबाव कुछ कम हो सकता है। भारत वित्तीय स्थिति को तत्काल नियंत्रित करने में सफल हो सकता है। लेकिन, अगर चलकर अर्थव्यवस्था में दोहरा दबाव भी पड़ सकता है। इस योजना के साथ कई जोखिम भी हैं। सबसे बड़ा खतरा विनिमय दर का है। पिछले कुछ वर्षों में डॉलर, लगातार रुपये के मुकाबले मजबूत हुआ है। भविष्य में रुपये की कमजोरी जारी रहती है, तो सरकार को बॉन्ड का भुगतान मांग के अनुसार करने पर ज्यादा डॉलर भुगतान करना पड़ेगा। इसमें सरकार को केवल व्याज ही नहीं, बल्कि विनिमय दर में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह स्थिति भविष्य में वित्तीय दबाव को और बढ़ा सकती है। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए केवल उधारी आधारित समाधान लंबे समय तक प्रभावी नहीं हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है, भारत को निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने, घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में ज्यादा ध्यान देना होगा। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, निर्यात

बढ़ाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में दीर्घकालीन ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। सरकार और रिजर्व बैंक को समझना होगा, विदेशी मुद्रा भंडार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह देश के आयात-निर्यात भुगतान के संतुलन तथा आर्थिक विश्वसनीयता का प्रतीक है। यदि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है तो संभालने के लिए बार-बार बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए डॉलर बॉन्ड तत्काल मलहम का काम कर सकता है। यह स्थायी समाधान नहीं है। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को बेहतर एवं मजबूत बनाना होगा। विदेशी मुद्रा भंडार आयात-निर्यात भुगतान संतुलन एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का भंडार होना ही चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से देश को अर्थ संकट का सामना कर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। विदेशी निवेशक भारत से भाग रहे हैं। निर्यात की तुलना में आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार के ऊपर देसी और विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। रुपये के मुकाबले डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में गंभीरता के साथ सरकार के अर्थ विशेषज्ञों और रिजर्व बैंक को जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा अन्यथा स्थिति कभी भी भयावह हो सकती है।

परीक्षार्थियों से खिलवाड़

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की पात्रता परीक्षा नीट के प्रश्नपत्र लीक होने से पूरी परीक्षा रद्द करने की मजबूरी जितनी शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक। यह परीक्षा इसलिए रद्द करनी पड़ी, क्योंकि राजस्थान पुलिस को कुछ छात्रों के पास से ऐसे गेस पेपर मिले, जिनके 410 प्रश्नों में से 140 से अधिक परीक्षा के मूल प्रश्नों से हूबहू मिल रहे थे। साफ है कि परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों ने परीक्षा के पहले ही कहीं से प्रश्नपत्र हासिल कर लिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और शीघ्र ही नीट का दोबारा आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 22 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी परीक्षा फिर से कराने का मतलब है छात्रों के साथ सरकार के समय और संसाधन की बर्बादी। छात्रों को मानसिक रूप से जो परेशानी उठानी पड़ी, उसकी तो क्षतिपूर्ति करना ही कठिन है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का गठन ही इसलिए हुआ था कि प्रतियोगी परीक्षाएं नीर-झीर ढंग से हों, वह अपने उद्देश्य में नाकाम सिद्ध हो रही है। नीट में गड़बड़ी और अव्यवस्था के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। गत वर्षों में कई बार इस परीक्षा में सेंध लगने के आरोप लगे और दो वर्ष पहले तो इन आरोपों ने इतना तूल पकड़ा कि एनटीए को कुछ केंद्रों की परीक्षा रद्द करके दोबारा करानी पड़ी थी। अतीत में एनटीए की ओर से आवोजन की जाने वाली कुछ और परीक्षाओं में भी गड़बड़ाइयां हो चुकी हैं या फिर धांधली की आशंका के चलते उन्हें टालना पड़ा है। स्पष्ट है कि यह एजेंसी कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इसकी तह तक जाना होगा कि ऐसा क्यों है। उसे इसका समाधान होना चाहिए कि एनटीए के साथ उसकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर इंटरनेट और कंप्यूटर के इस युग में किसी परीक्षा के प्रश्नपत्र मुद्रित कर उन्हें देश भर के सैकड़ों केंद्रों में भेजने की पुराने जमाने की प्रक्रिया क्यों जारी है।



# Mental health priorities for the new Kerala government

In an interview, newly elected MLA Ramesh Pisharody called for a dedicated ministry for mental health. Currently, most activities fall under the Ministry of Health, while others are scattered across departments.

The mental health of school students is managed by the education department and the Ministry of Women and Child Development. Then there are the police-run student well-being and digital de-addiction initiatives. The excise department handles de-addiction programmes, the Ministry of Youth Welfare pilots youth mental health projects, and women’s well-being initiatives are under the Women’s Welfare Ministry.

Despite numerous programmes, there is little focus, coordination, or impact auditing. With several psychosocial issues signalling declining mental health in Kerala, the MLA’s vision for a unified ministry is timely and relevant.

The burden of mental illness in Kerala

The 2016 National Mental Health Survey found that 11.36% of people in Kerala had a mental disorder at the time of the survey, with a lifetime prevalence of 14.14%. Roughly one in eight people in the state need mental health intervention — higher than national averages. Common conditions include anxiety and stress-related disorders at 5.43%, depression at 2.49%, and substance use disorders at 4.82%. Are they all getting the help they need?

Access versus stigma

Kerala has relatively better mental health care in both the government and private sectors. However, gaps exist in Wayanad and Idukki districts. Yet stigma and shame prevent many from seeking scientific treatment.

Quacks exploit this reluctance, diverting people from professional care. The government must regulate unqualified practitioners in mental health services. This includes mandatory licensing of counselling centres with clear qualification standards. Stigma-reduction campaigns are essential to convey that mental disorders are health conditions like any other, and that there is no health without mental health.Modernising services

The three mental health centres in Thrissur, Kozhikode and Thiruvananthapuram, functioning well amidst constraints, should be modernised and made patient-friendly, possibly using corporate social responsibility funds.A Centre of Excellence for addiction treatment could be integrated with one of them. Such a centre is urgently needed as addiction-related problems rise in the state. It should develop evidence-based protocols and monitor other de-addiction centres across the state. Although the Mental Healthcare Act mandates registration, many de-addiction centres still operate outside such controls. Psychiatric services at district and taluk levels can be upgraded qualitatively without overwhelming financial burden. What is needed is vision and innovation.The District Mental Health Programme requires revision with broader objectives and a stronger focus on community-based treatment and rehabilitation. Residential rehabilitation centres should be audited regularly by DMHP teams, which might require additional manpower.

# Separating business of war from economics of oil

The US’s extension of relief for Russian oil and hint of easing pressure on Iranian supplies may presage a new sanctions regime. It will take months to achieve pre-war supplies

With the US-Iran conflict moving into its third month, an ominous suspense pervades global energy markets. The blockade of the Strait of Hormuz has halted the flow of a fifth of the world’s oil and liquefied natural gas supplies, and triggered the largest energy disruption in history. With more than a billion barrels of oil already lost, the soaring benchmark crude prices are maintaining an extreme upward pressure on refined products like diesel and jet fuel, with a cross-sectoral effect. The shortage of sulphur (a by-product of crude oil and gas processing critical for fertiliser production) and loss of fertiliser shipments from the Persian Gulf could affect global food security. Stalled projects and job losses are inevitable as cost cutting becomes unavoidable. The economic pain is sure to prevail at all income levels.Efforts to artificially stabilise markets and curtail inflation shocks prompted major oil consumers and the International Energy Agency—comprising 32 member, 13 association and six ‘accession’ countries—to initiate a historic release of strategic reserves. One of the criteria for the agency’s membership is the “capability of contributing its share of an IEA collective action which would be initiated in response to a significant global oil supply disruption and would involve IEA member countries making additional volumes of crude and/or product available to the global market (either through increasing supply or reducing demand)”. Out of the pledged release of 400 million barrels, 164 million barrels have already entered the global markets, according to the latest IEA report.

Saudi Aramco and Abu Dhabi National Oil Company bypassed the choked maritime route and partially mitigated the loss of supply through alternative overland pipelines. However, these supply measures proved insufficient in addressing price volatility. On the other hand, demand curtailment is only a temporary panacea as stockpiles are fast depleting and parleys between the combatants are failing to make headway.Most developed and emerging economies hold strategic petroleum reserves (SPRs) to enhance energy security in periods of exigency. Japan and South Korea follow a public-private partnership for their SPRs, leasing underground storage facilities to domestic private refineries under mandate and foreign oil producers like ADNOC that maintain huge stocks with a right to export

a portion of it with the host country having the first right of refusal. India partnered with ADNOC to store crude at two State-owned strategic underground facilities in India, with a third site under development with a total capacity of 30 million barrels when fully operational. At current demand, it translates to seven days of stocks, far below the 90-day benchmark set by the IEA. Yet, it lays a roadmap for future expansion and a PPP model.

The UAE’s exit from Opec on May 1, in the midst of the Iran war, added complexity to an uncertain market. Though the fourth largest member’s walkout initially fuelled a fear of group politics, a more sanguine picture has emerged since. Relieved of quota restrictions, as it aims to enhance production to 5 million barrels per day,



Abu Dhabi has accelerated construction of a West-East Pipeline to Fujairah, bypassing the Strait of Hormuz. Slated to be operational by 2027, it shall double the Emirati oil export capacity and substantially slake Asia’s thirst.Meanwhile, Brazil has reported much larger volumes of crude exports to Asia during the present disruption. As mentioned in this column last November, with rising production volumes at the Tupi and Buzios offshore assets of Petrobras, the low-sulphur Brazilian-grade crude has captured a larger portion of the Asian markets. Despite freight constraints, its share in China’s imports rose to 18 percent in April from less than 10 percent in January. On the back of well-negotiated prices, the Latin American medium-sweet crude has expanded its presence in the Indian energy mix, too. Besides State-owned refineries, Reliance remains a key

buyer in the spot market for Brazilian crude and accounts for a major portion of Petrobras’s oil shipments to Asia.However, African sources such as Nigeria, Angola and Libya have provided limited succour to Europe and Asia. Despite holding the 11th largest reserves in the world, Nigeria’s oil industry, with many small refineries, is vulnerable to several operational and security hurdles. The sector, which has historically battled under-investment, pipeline vandalism and poor turnaround maintenance, is prone to outages. However, the Lagos-based Dangote refinery, Africa’s largest with a capacity to process 650,000 barrels a day, has significantly increased shipments of jet fuel and diesel to Europe to partially fill the supply gaps caused by the West Asian tensions.

Donald Trump’s recent visit to Beijing emerged as Washington’s diplomatic overture, suggestive of a meeting between two equals rather than a competition for global supremacy. With the grim energy situation in the background, and in a bid to pursue the G2 framework, Trump followed up on the discussions with Xi Jinping with a hint of easing sanctions on Chinese independent ‘teapot’ refineries that process Iranian crude. Hengli Petrochemical, China’s second-largest teapot refinery, is considered to be one of Tehran’s largest customers for crude, as per a US Treasury report.

Coming amid an escalating geopolitical showdown, the development is viewed as an effort to manage global oil dynamics as much as heralding a new phase in US sanctions policy. Could the move legitimise Iranian oil’s continued presence in Asian markets and the ‘shadow fleets’ that facilitate such transits, as Washington woos Beijing to broker peace? It seems America is keen to segregate its business of war from the economics of oil by any means.Given the current global shortage and China’s continued oil trade with Russia, the US Treasury extended the Russian oil waiver a second time. The continued flow of Urals is expected to temporarily stabilise the crude market and provide renewed energy security to the two largest consumers, China and India. The move shall augment supply of sulphur and other oil derivatives, enabling a surge in fertiliser production.Few analysts predict the war to end by early June. Markets absorb this with cautious optimism as it may take months of normalisation to touch pre-war volumes. While new sources of oil emerge and their durability remains restricted, a collective initiative of nouveau rentiers might just bail out the situation.

## Simultaneous polls: Potential benefits not enough to build consensus

The JPC must take diverse factors and perspectives into account before submitting its findings on One Nation, One Election issue

A Joint Parliamentary Committee is holding nationwide consultations on two Bills related to the politically divisive issue of ‘One Nation, One Election’ (ONOE). PP Chaudhary, the BJP MP who is heading the multi-party panel, has stated that India can save Rs 7 lakh crore if Lok Sabha and Assembly elections are held simultaneously. According to him, this exercise would raise the country’s GDP by 1.6 per cent and the money saved can be used for development works and welfare schemes. There is no quarrel with the argument that ONOE would lead to considerable savings in terms of money, time and manpower. However, there is much more to electoral democracy than convenience and cost-benefit calculations.The Congress and many other Opposition parties are calling simultaneous polls an attempt by the BJP-led Union government to centralise power and undermine the federal structure. These concerns have only grown

after the saffron party added West Bengal to its burgeoning kitty of states. The Centre, however, is



insistent that ONOE will benefit the nation. The lack of consensus makes it vital for the parliamentary

committee to engage with a wide range of stakeholders — political parties, constitutional authorities, legal experts, administrative bodies, financial and educational institutions, industry and civil society.One of the biggest challenges is to synchronise elections — different states go to the polls in different years. Also, there has to be a concrete plan for the worst-case scenario — when a government falls mid-term due to defections or a no-confidence motion. Moreover, Lok Sabha elections focus on national issues, while Assembly battles primarily revolve around state/regional matters. Clubbing the two contests may give an unfair advantage to the ruling party at the Centre, especially in states where it is not in power. The panel must take diverse factors and perspectives into account before submitting its findings. After all, the proposal, if implemented, will have far-reaching implications for India’s democratic and federal framework.

# DNA science and the quest beyond ageing

## The near-future of genomics lies in its convergence with AI and spatial omics

FRONTIER technologies are fascinating. In these columns, I have tried to provide a glimpse into the worlds of artificial intelligence, quantum computing, internet of things and renewable energy. Today, we delve into the enigmas of genomics.On September 3, 2025, a hot mic caught Vladimir Putin, Xi Jinping and Kim Jong Un musing about organ transplants, biotechnology and the possibility of living to ‘a’ young 150. Three of the world’s most powerful totalitarians are not any different from other world leaders and business tycoons when it comes to battling age. The twin enigmas of ageing and death, however, remain, arguably, the final unconquered bastions of biological science. While we have dismantled the atom, decoded the cosmic microwave background and engineered pathogens to deliver therapeutic payloads, the programmed obsolescence of our own cellular machinery eludes a definitive, mechanistic solution. This pursuit, the deep interrogation of our biological operating system, is unfathomable without genomics.At its foundational level, genomics is the study of the genome, an organism’s complete set of deoxyribonucleic acid (DNA) — the chemical repository of the instructions needed to develop, operate and perpetuate virtually every living organism. Its double helix comprises two anti-parallel strands, each a string of four nucleotide bases: adenine (A), thymine (T), guanine (G) and cytosine (C). The strands are complementary; A always pairs with T and C with G. The linear sequence of these billions of letters encodes the instructions for building and operating a human body.A gene, a specific locus on DNA, carries the code for a functional product, typically a protein. Information flows from DNA to a transient messenger molecule, messenger ribonucleic acid (mRNA), through the process of transcription. This

mRNA transcript then exits the nucleus and engages the ribosome, a molecular machine that translates the nucleic acid code into a specific sequence of amino acids, which fold into a 3D protein. Proteins form organs, catalyse biochemical reactions, and relay signals.When a somatic mutation alters this sequence, an aberrant protein can be produced, disrupting homeostatic networks and potentially initiating a pathological cascade, such as neoplasia. Genomics, therefore, is the science of reading, interpreting, and now, editing this fundamental text.The impact of this ability is already transformative and pervasive across multiple sectors. In clinical medicine, genomics has catalysed the shift from empirical, population-based protocols to personalised and predictive paradigms. Pharmacogenomics, the study of how genetic variation affects drug response, allows clinicians to pre-empt adverse reactions and choose the right drug at the right dose from the outset.Genomic sequencing is now the definitive tool for tracking disease outbreaks. When a new pathogen emerges, decoding its genome allows scientists to understand its origins, monitor its mutations in real time and develop targeted diagnostics and vaccines with unprecedented speed.The same logic applies to rare diseases: India bears a significant burden of rare diseases. Around one in every 20 Indians is affected by 7,000 to 8,000 diseases classified as rare. Genomic sequencing is increasingly the first-line diagnostic tool, ending diagnostic odysseys that previously lasted years.This capability is inseparable from food security, which is inextricably linked to national security. Genomics is revolutionising agriculture by enabling the development of crops with higher yields, enhanced resistance to pests and drought and improved nutritional content, all critical factors for a

stable and secure food supply in the face of climate change. Similarly, genomic analysis of soil microbes can inform more sustainable farming practices and the monitoring of biodiversity loss.In the realm of biosecurity, genomics provides the sentinel system,



allowing for the rapid characterisation of engineered pathogens in a bio-attack scenario and the subsequent design of gene-specific medical countermeasures, such as mRNA vaccines or monoclonal antibodies.Even in the domain of criminal justice, DNA analysis through forensic genomics not only helps identify suspects with high precision but also resolves cold cases by tracing distant familial connections through public ancestry databases, a technique that led to the apprehension of the ‘Golden State Killer’ of the US.Concurrently, the commercial translation of genomics is accelerating globally. The worldwide genomics market, estimated to be valued around \$30-40 billion, is on a steep growth trajectory, and India’s market is projected to mirror this with a CAGR of 16.6%, reaching an estimated \$1.86 billion by 2033.However, this scientific and commercial momentum generates a series of profound

policy and legal frictions. The most immediate challenge is the governance of the direct-to-consumer testing market, which operates in a near-regulatory vacuum. Companies can directly market single-gene, multi-gene and even exome-sequencing services to consumers without a mandated framework for analytical validity, clinical validity, or, most critically, the post-test return of results. The interpretation of a polygenic risk score for a complex disorder like type 2 diabetes or the discovery of a variant of uncertain significance requires nuanced clinical translation alongside non-directive genetic counselling.The very nature of genomic data places it in a category distinct from other medical information, demanding a rethinking of the data protection framework. A genome is a permanent, personally identifiable blueprint that contains predictive information not only about the individual but also about their kin. The Digital Personal Data Protection Act, 2023, fails to recognise "genetic data" as a specially protected category with heightened safeguards. The Act’s "consent" framework for scientific research is philosophically mismatched with the highly sensitive, re-identifiable nature of genomic data. This creates an incongruous scenario where the country is generating vast population-scale genomic datasets through initiatives like the Genome India Project, which are managed under the normative Framework for Exchange of Data (FeED) protocols of the Biotech-PRIDE Guidelines, while the statutory law governing the privacy of this data remains generic.

The near-future of genomics lies in its convergence with AI and spatial omics. The sheer volume of data produced by a single human genome is staggering, and making sense of it is a computational grand challenge.



Rupee rallies 63 paise to close below 96 level

New Delhi,.(Agency) Rupee strengthened for a second straight session on Friday, rising 63 paise to close at 95.73 on the back of easing crude prices, positive equity markets, and softer US yields coupled with the intervention from central bank.

Rupee opened at 96.30 in the interbank foreign exchange market on Friday and continued to remain in the green territory and touched an intra-day high of 95.30 and a low of 96.68 before settling at 95.73. The latest rise comes after the currency had rebounded 50 paise on Thursday from its record closing low to end at 96.86 against the greenback on Wednesday after falling to 96.96 intraday. Forex traders said the Reserve Bank was active in the market throughout the day. The \$5 billion swap announced for May 26 also kept the punters at bay. Another enabler is the falling bond yields and easing geopolitical tension that have softened crude prices. Benchmark stock indices ended the session in positive territory, with the Sensex rising 231.99 points and the Nifty advancing 64.60 points.

Radhika Rao, senior economist at DBS Bank, said the rally in rupee is due to the Reserve Bank reviving monetary operations to slow rupee’s fall, after the currency came within touching distance of a record low of 97 earlier this week. She said a closer scrutiny of outbound FDI and encouraging exporters to channel proceeds to the onshore markets might be pursued.In the run-up to the monetary policy review in early June, markets are likely to increasingly price in the likelihood of a hike, especially if the rupee remains under pressure and a resolution on the Iran war proves to be elusive, she added. The rupee maintained its upward momentum for the second straight day, effectively reversing the losses sustained at the start of the week, Dilip Parmar senior analyst at HDFC securities said and attributed the rally largely to the Reserve Bank’s active market intervention post the announcement of its dollar swap, alongside a reprieve in crude prices as geopolitical risks eases.

IPO market loses steam: Only Rs 56,000 raised so far; when can it revive?

Kolkata ,(Agency) The current calendar year has witnessed a sharp deceleration in the IPO market while expert agencies predicted a sharp acceleration. Some agencies even predicted that 2026 will go down in history as a bumper year when the number of primary issues will be the highest in a year ever and also raise a very high amount of money that could even reach close to the fantastic number of Rs 4 lakh crore. Against that estimate, the current year has witnessed only 20 mainboard listings and 62 SME IPOs. The mood among investors has been so low that about 150 companies are waiting in the sidelines to float their IPOs even after getting the final nod from market regulator Sebi. As the US-Iran war rages on without no solution to the blockade of the Strait of Hormuz, the only hope of the IPO market reviving somewhat is pinned on a few mega IPOs such as NSE, Jio Platforms and Zepto. This might happen only in the second half of the year.

Amount collected in 2026 so far According to published data, about Rs 56,322 crore has been raised through IPOs this year. In the same period in 2025, as much as Rs 82,678 crore was mobilised from the market. The amount mopped up this year appears optimistic only when compared with that in 2023, when only Rs 12,281 crore was raised during the same period. Significantly, 2023 was year when the primary market faced obstacles in the form of too high corporate valuations and weak stock performance after listing which injected circumspection among investors.

World stares at 2008 like recession, crude oil prices may reach \$200 if Hormuz remains closed: Reports

New Delhi.(Agency) With US-Iran war tension shows no signs of abating, the global energy market remains in throes indicating a downturn in massive world economies. The shock US attack on Iran on February 28 is about to complete three months on May 28 and with this the Strait Of Hormuz, the global chokepoint from where one-fifth of the global energy passes, is also shut.Meanwhile, a report from the global research firm, Wood Mackenzie, has warned of dire economic consequences if the Strait of Hormuz remains shut for longer period. Crude price may reach \$200 per barrel The prices of crude oil may reach as high as \$200 if blockade remains in place, a report in Economic Times said citing Wood Mackenzie report. Since the US-Israel attack on Iran, the global energy market is on the edge with growing fears of inflation prompted by high crude oil price. The prices of Brent crude reached it peak of \$120 per barrel since the attack. Before the war, prices hovered around \$72. Global supply chain at risk As per the Wood Mackenzie report, the war in West Asia and the subsequent closure of Hormuz has drastically disrupted the global supply chain and is likely to hit the economies hard.The report also maintained that 20 percent of the world's LNG supply, which amounts to 80 million tonnes per annum has also been affected by Hormuz closure. Rapidan Energy group predicts 2008 like recession In yet concerning report, the Rapidan Energy Group has predicted 2008 like global recession if the Hormuz remains affected by the US-Iran war. The energy research group also assesses that if the oil shock continues beyond July, then there is a possibility of drop in oil demand to balance the demand for August and September.

FII's remain net seller this week, domestic investors provide cushion

In the month of May, FIIs have sold a cumulative Rs 32,230 crore, while DIIs have bought Rs 56,870 crore, based on provisional exchange data.

New Delhi,.(Agency) Foreign institutional investors (FIIs) remained net sellers this week, offloading Rs 7,570 crore based on provisional exchange data as domestic institutional investors (DIIs) were net buyers, purchasing Rs 16,950 crore, providing enough cushion. In the month of May, FIIs have sold a cumulative Rs 32,230 crore, while DIIs have bought Rs 56,870 crore, based on provisional exchange data."However, they turned net seller in the remaining four sessions of the week



with outflow of Rs 10,380 crore. DIIs remained net buyer in all the five-trading session during last week with net inflow of Rs 16,950 crore," said Pabitra Mukherjee, Associate Vice President-Research, Bajaj Broking.Benchmark indices traded choppy with high volatility swinging between gains and losses as investors navigated heightened market uncertainty and mixed cues across

sectors.Nifty during last week traded in the broad range of 23,300-23,850, with the index testing the upper and lower band on multiple occasion and finally close the week at 23,719 levels, up by 0.3 percent. According to analysts, the currency backdrop continues to remain a structural concern. Despite resilience in global equities, the Indian rupee continues to

trade near weak levels against the US dollar.Persistent currency weakness not only heightens imported inflation risks but also keeps foreign institutional investors cautious towards emerging markets such as India. "As a result, broader market stability continues to rely significantly on domestic institutional inflows absorbing periods of FII-led selling pressure," they said.Investor sentiment remained cautious due to persistent geo-political tensions, which continued to keep crude oil prices elevated.Meanwhile, a sharp rise in bond yields, driven by concerns over rising inflation and the possibility of prolonged higher interest rates, kept investors on edge.Overall, global uncertainty and macroeconomic headwinds led to cautious trading activity across the markets. Looking ahead, institutional flows are likely to remain sensitive to developments around US–Iran tensions, oil-price movement, said analysts.

Petrol price raised by 87 paise, diesel by 91 paise; third hike in 10 days

New Delhi.(Agency) Petrol and diesel prices were hiked again across India on Saturday, with petrol increasing by Rs 0.87 per litre and diesel by Rs 0.91 per litre. This marks the third upward revision in retail fuel rates this month by the state-owned oil companies amid sustained pressure from rising global crude oil prices and geopolitical tensions in West Asia. In Delhi, as per a PTI report, petrol prices were raised by 87 paise per litre, increasing from Rs 98.64 to Rs 99.51, while diesel prices went up by 91 paise from Rs 91.58 to Rs 92.49 per litre.

The hike comes a day after the Ministry of Petroleum and Natural Gas had assured that, despite rumours, India has adequate petrol and diesel supplies. "India has adequate availability of petrol and diesel supplies across the country continue to remain stable. Citizens are advised to avoid panic buying and purchase fuel only as per actual requirement. Temporary pressure at some retail outlets is being addressed through continuous supply monitoring and coordinated distribution efforts by Oil Marketing Companies," read a tweet by the ministry.It also further

added that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for everyone during the ongoing high-demand period.On May 16, India saw a



significant rise in its fuel prices after the state-run oil companies revised them, raising petrol and diesel rates by around Rs 3 per litre in several cities.Following this, prices again saw a 90 paise increase in all metros on May 19. With the latest increase, fuel prices have risen by nearly Rs 5 per litre over the period.The fresh hike is likely to put additional pressure on commuters, transporters and businesses across multiple sectors. Experts have warned that repeated increases in petrol and

diesel prices may lead to higher transportation and logistics costs, which could eventually push up the prices of essential goods and food items.Government officials, however, maintained that the revisions are essential to offset rising import costs and ensure stability in fuel supplies amid ongoing geopolitical tensions and uncertainty in international energy markets.India relies on imports for nearly 85 per cent of its crude oil requirements, making domestic fuel prices vulnerable to fluctuations in global markets. Growing concerns over possible disruptions in the Strait of Hormuz, one of the world's most crucial oil transit routes, have further intensified fears of supply shortages.Meanwhile, CNG and PNG prices have also been revised upward in several cities in recent days, adding to concerns over inflation and increasing household expenses.

Compressed Natural Gas (CNG) prices in Delhi have been increased by Re 1 per kilogram, adding to the burden on commuters and commercial vehicle operators amid rising fuel costs.

Govt urges people to use electricity judiciously as heatwave pushes power demand to record high

New Delhi,.(Agency) Amid growing demand for electricity due to heatwaves in the country, power ministry on Friday urged citizens to use electricity judiciously. The ministry, however, said though there is no shortage of electricity, it should be used wisely.In the last four days, electricity demand has broken all previous records due to the searing heat across the country, which has led to increased use of cooling devices by people. In fact, the peak power demand has even crossed the estimated 270.82 GW, the highest so far, surpassing the ministry’s projection of peak power demand in the country.Over the past four days, power demand has continued to rise. For instance, the peak power demand met on May 18 was 257.37 GW, on May 19 it was 260.45 GW, on May 20 it reached 265.44 GW, and on May 21 it hit the

highest level of 270.82 GW. "The peak daytime demand usually occurs between 2 PM and 4 PM. Although we are prepared to supply electricity as required, due to the



intense summer, let us all try to use electricity wisely and judiciously," said the Power Ministry in a social media post on X.The spike in electricity consumption comes amid severe

heatwave conditions across northwest and central India. According to the India Meteorological Department, temperatures in several regions are nearing the 45-degree Celsius mark. Last summer, India recorded a peak power demand of 242.77 GW in June 2025, although it remained below the government’s projected estimate of 277 GW.In May 2024, the country’s peak power demand had touched 250 GW, surpassing the previous record high of 243.27 GW recorded in September 2023.According to the ministry, the peak demand was met through a diversified energy mix comprising 59 GW from solar power, 14 GW from wind energy, 15 GW from hydro power, 169 GW from thermal power, 2.386 GW from gas-based generation, and 7.20 GW from nuclear power.



and outward FDI, which, according to him, reflects Indian corporates maturing internationally rather than being a vote against India, “but a line that deserves far sharper disaggregation than it has received”. However, the RBI said that with the recent correction in financial asset valuations, it expects repatriations to moderate, improving the net capital account position going forward. Meanwhile, the central bank said in its blletin that global economic conditions remained fragile, shaped by heightened geopolitical tensions, elevated energy costs and persistent uncertainty surrounding the growth and inflation outlook. “The near-term outlook is somewhat clouded by supply-side pressures. Although headline inflation remains firmly within the tolerance band, the pass-through to domestic prices needs to be monitored. Financial conditions, crude oil prices and capital flows continue to pose challenges to the external sector outlook,” the RBI said in its monthly report.

Kevin Warsh sworn-in as Federal Reserve chair, Trump wants him to be 'independent'

Speaking at the White House East Room ceremony on Friday, Trump called Warsh "one of the truly great chairmen of the Federal Reserve that we've ever had".

New Delhi.(Agency) President Donald Trump swore in Kevin Warsh as Chairman of the Federal Reserve Board and said he would restore confidence in the US' Central bank. Speaking at the White House East Room ceremony on Friday, Trump called Warsh "one of the truly great chairmen of the Federal Reserve that we've ever had".He's respected by everybody, and that's so important in that position," the US President said.Warsh took the oath of office from Supreme Court Justice Clarence Thomas before an audience that

included House Speaker Mike Johnson, Treasury Secretary Scott Bessent, Commerce Secretary Howard Lutnick and former Secretary of State Condoleezza Rice.Trump said he wanted Warsh to operate independently.

"I want Kevin to be totally independent," he added."Don't look at me, don't look at anybody, just do your own thing and do a great job."The US President criticised the Federal Reserve's recent direction. He said the institution had become distracted by "climate policy and Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) initiatives" instead of focusing on inflation and employment.Trump also praised Warsh for supporting reforms at the central bank."He'll bring much needed reform and modernisation," Trump said, referring to data collection, economic modelling and the Fed's communication practices.

Warsh said the Federal Reserve must remain focused on price stability and maximum employment."Our mandate at the Fed is to promote price stability and maximum employment," he added."When we pursue



those aims with wisdom and clarity, independence and resolve, inflation can be lower, growth stronger, real take-home pay higher, and America can be more prosperous." He pledged to lead what he called a "reform-oriented Federal Reserve". "I will lead a reform-oriented Federal Reserve learning from past successes and

mistakes," Warsh said.Trump used the event to promote his administration's economic record.He said the stock market had hit new highs during trading on Thursday.

"Stock market's up 600 points," Trump said. "That means they like you."President Trump also said the United States had attracted "\$18 trillion being invested in the US" during the first 11 months of his administration.He credited tariffs and deregulation for driving manufacturing and technology investment."We're building factories, car plants, everything, AI, everything all over the country," Trump said."Nobody's ever seen anything like it."Warsh previously served as a Federal Reserve Governor during the 2008 financial crisis.Trump said he studied under economist Milton Friedman and was mentored by former Treasury Secretary and Secretary of State George Shultz



# More than 20 heatstroke cases reach hospitals as capital simmers at 43°C

**New Delhi.(Agency)**  
As temperatures continued to soar under an orange alert, the capital witnessed a worrying rise in heat-related illnesses, with at least 15 to 25 cases reported across city hospitals on Friday, doctors said.  
A day after two heatstroke patients were admitted, medical professionals noted that cases are now emerging from different parts of the capital, signalling the early impact of the ongoing heatwave.  
Dr Sanjay Sood, senior medical officer at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, said, “Heat wave cases have started reaching hospitals... around 15 to 25 cases have already started coming



in.”He added that the confirmed cases of heatstroke, one of the most severe forms of heat-related illness, have already been reported, raising

concerns among the healthcare providers. The gravity of the situation is evident at RML Hospital, where two patients admitted on May 21 highlight the dangers of prolonged exposure to extreme heat.  
Dr Ajay Chauhan, director and professor of medicine at RML, detailed their condition.  
“A 24-year-old man, arrived unconscious with a body temperature of 105°F and remains critical on ventilator support despite immediate cooling treatment,” he said. “Another patient, brought in later, responded well and is now stable,” he added.  
Doctors warned that heatstroke can escalate rapidly and may prove fatal if not treated promptly. With

neighbouring regions such as Noida and Ghaziabad already under red alert, indicating severe conditions, health experts caution that number of cases could rise sharply in the coming days.  
**Heatwave till May 28: IMD**  
IMD retained its alert for heatwave conditions in the capital till May 28. Safdarjung, the city’s base weather station, recorded a maximum of 43.3 degrees Celsius on Friday. Delhi government and the IMD have been urging the residents to take precautions, including staying hydrated, avoiding direct sun exposure during peak hours, and seeking immediate medical attention if symptoms of heat exhaustion or heatstroke appear.

## Delhi HC issues notices to AAP leader Gopal Rai, journalist Saurav Das in judge contempt case

**New Delhi.(Agency)**  
The Delhi High Court on Friday appointed senior advocate Rajdipa Behura as amicus curiae for assistance in contempt proceedings initiated against AAP leaders Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and others.Behura previously served as the Delhi government’s additional standing counsel and the CBI’s special public prosecutor. She was designated a ‘senior advocate’ in 2024.  
The bench—comprising Justices Navin Chawla and



Ravinder Dudeja—also issued notices to AAP leader Gopal Rai and journalist Saurav Das on a plea seeking contempt proceedings against them over an alleged “orchestrated social media campaign” against Justice Swarana Kanta Sharma.  
The bench had earlier issued notice to Kejriwal and others on a contempt case initiated suo motu by Justice Sharma. The court has listed the matter for hearing on August 4.  
The petition, which has been filed by advocate Ashok Chaitanya, alleges that Rai and Das had attempted to exert “extra-judicial pressure” on Justice Sharma through social media posts while Kejriwal’s recusal plea in the excise policy case was pending.

## Viral 'Donald Trump' buffalo to be slaughtered on Eid-al-Adha in Bangladesh

**New Delhi.(Agency)**  
An albino buffalo that went viral for its resemblance to United States President Donald Trump is set to be sacrificed in Bangladesh during Eid al-Adha after drawing huge crowds and becoming a social media attraction ahead of the festival.The nearly 700-kg buffalo, raised at a farm in Narayanganj near Dhaka, earned the nickname "Donald Trump" because of the blond tuft of hair falling across its forehead, which many compared to the US President's signature hairstyle.  
Farm owner Ziauddin Mridha said the animal had already been sold to a customer for sacrifice during Eid al-Adha, one of the most significant Islamic festivals marked by the ritual sacrifice of livestock.  
"I am going to miss Donald Trump, but that is the core spirit of Eid al-Adha -- making a sacrifice," Mridha told news agency AFP.The four-year-old albino buffalo became an internet sensation over the past few weeks, with visitors arriving daily to take selfies and videos with the unusually coloured animal. Many travelled from distant districts to see the buffalo, while children crowded outside the farm gates hoping for a glimpse.  
Mridha said his younger brother came up with the nickname after noticing the buffalo's flowing blond hair. He described the animal as gentle and calm by nature, adding that albino buffaloes are generally non-aggressive unless provoked.  
The buffalo required special care, including four baths a day and multiple meals to maintain its health before Eid, according to the owner. However, he said the constant crowds and attention had also caused stress to the animal, leading to weight loss and restrictions on public viewing.  
Livestock officials said albino buffaloes are extremely rare in Bangladesh because of a lack of melanin, giving them their pale skin, pinkish nose and light-coloured hair.

## Delhi court raps police over 'concocted' investigation while granting relief to 12 accused in 2007 'rioting' case

**New Delhi.(Agency)**  
A Delhi court on Friday discharged 12 surviving accused in the 2007 Jamia Nagar rioting case, rapping the prosecution for “concocted investigation” having “stock involvement of police witnesses” for identification, while terming several arrests as “contrived.”

In a 95-page order, Special Judge Vishal Gogne, who also ordered framing of charges against 13 accused, further slammed Delhi Police for serious lapses, particularly the failure to conduct a test identification parade, which he termed a “requirement of essence and not just prudence”.  
According to the prosecution, on September 22, 2007, a riotous mob



of around 1,500 people attacked the Jamia Nagar police post personnel. It said the local police had taken steps to remove a market which was allegedly creating a hindrance to people going for offering Namaz during the month of Ramzan.  
The prosecution claimed that 12 local leaders instigated the mob to kill the policeman and burn down the police station, following which the post was set ablaze, several vehicles

were torched, a service pistol, 10 live cartridges, valuables and a wireless set were looted, and multiple police officials were injured, of whom five suffered grievous injuries.  
The judge rapped the prosecution while discharging the accused persons.  
He said, “In the present investigation, it does weigh with the court that not only did the police officials avoid conducting a test identification parade (TIP) of the 11 persons who were arrested at the identification of at least two police persons each; the investigating officer (IO) even failed to consider the possibility of seeking arrest upon identification by one police witness while enabling TIP through the second police witness.”

## Transport Union strike affects supply chains, daily commute

**New Delhi.(Agency)**  
A three-day transport strike called by over 68 transport unions under the All India Motor Transport Congress (AIMTC) severely disrupted transportation and supply chains across Delhi-NCR as it entered its second day on Friday.  
The protest, involving trucks, taxis, autos, and other commercial vehicles, was launched against the Delhi government’s hike in the Environmental Compensation (Green) Cess and the growing operational burden caused by the rising fuel prices.  
The strike affected the movement of goods and commuters across the capital, with disruptions visible at major transport hubs and wholesale markets. Among the worst-hit areas was Sanjay Gandhi Transport Nagar. Normally, around 4,000 to 5,000

trucks operate daily from this area, but during the strike, several loaded trucks remained parked along roads as drivers waited for transport operations to resume.The impact also



extended to Azadpur Mandi, Asia’s largest fruit and vegetable wholesale market. Traders reported delays in the arrival of essential goods due to the blockade. According to vendors, the

supply has been disrupted heavily.  
“Trucks are unable to reach the mandi because of the strike. Even the supply of available stock is getting affected since smaller goods vehicles are not operating normally. This is the reason some vegetable prices are overpriced,” one of the vendors said. Meanwhile, a distributor affected by the strike said the disruption has created serious challenges in maintaining supply timelines and fulfilling customer commitments.  
“The ongoing transport strike has created major disruptions in our day-to-day operations. Deliveries are getting delayed, dispatch schedules have been affected, and several orders are pending. This is impacting business operations and causing financial strain,” the distributor said.

## Delhi records peak power demand at 8,231 MW; a three-time jump from 2021

**New Delhi.(Agency)**  
On May 21 this year, Delhi recorded a peak power demand of 8,231 MW, its highest ever for the date, marking a drastic rise from just 2,783 MW on May 21, 2021, according to official data. In six years, the city’s electricity demand on the corresponding day has nearly tripled, underlining the sharp heat-driven power consumption.According to the official data of the Ministry of Power, the power demand never touched the 8,000 mark in the month of May in the past six years.  
The data shows a steady climb each year, from around 7,726 MW in 2024 and 7,748 MW in 2025 to over 8,200 MW in 2026. The rise has been sharp and relentless. While 2023 and 2024 saw demand largely hover between 4,000 and 6,500 MW, 2025 pushed the ceiling further to over 7,700 MW. This year,

however, has broken all previous records within weeks, with demand crossing 8,000 MW almost daily.  
An official from the BSES said, “The surge is being driven by intensifying heatwaves, with longer and hotter days and increasingly warmer nights forcing residents to depend heavily on air-conditioners, coolers and fans. What was once a peak seen occasionally in late June is now becoming routine as early as mid-May.”  
Between May 1 and May 21, Delhi’s peak power demand in 2026 was higher than the corresponding day of 2025 on 16 out of 21 days, around 76 per cent of the days. Compared to 2024, Delhi’s peak demand in 2026 was higher on 14 out of 21 days, around 67 per cent of the days. As the country’s daytime peak power

demand also touched an all-time high of 270.82 gigawatts (GW) on May 21, the Ministry of Power on Friday stated that electricity consumption has broken



previous records for four consecutive days due to intense summer conditions. In a post on X, the ministry has urged the citizens to use the electricity wisely. The ministry said in the post, “Although we

are prepared to supply electricity as required, due to the intense summer, let us all try to use electricity wisely and judiciously.”  
Even when the demand is expected to go up further in the coming days, the BSES officials stated that they are fully geared up to ensure reliable power supply to more than 53 lakh consumers and nearly 2.25 crore residents across the city. The power demand in the city is expected to witness further rise this summer.  
Additionally, around 2,670 MW of green power will play a key role in ensuring reliable electricity supply during the summer months in BSES areas, said officials. On the other hand, Tata Power-DDL also supplied the season’s peak demand of 2220 MW to date seamlessly across its network.



## NEWS BOX

## Eight dead, dozens trapped in China coal mine blast



BEIJING. (Agency)

At least eight people have died and dozens are trapped underground after a gas explosion at a coal mine in northern China, state media reported on Saturday. The blast occurred at 7:29 pm (1129 GMT) on Friday at the Liushenyu coal mine in Shanxi province, according to state news agency Xinhua.

A total of 247 workers were underground at the time, of whom 201 had been brought to the surface safely as of 6:00 am on Saturday, Xinhua said. Eight people have been confirmed dead, while 38 remain trapped underground, the agency reported, citing local emergency management authorities.

President Xi Jinping urged "all-out efforts" to treat the injured and called for thorough investigations into the incident, Xinhua said. He "emphasised that all regions and departments must draw lessons from this accident, remain constantly vigilant regarding workplace safety... and resolutely prevent and curb the occurrence of major and catastrophic accidents".

Rescue efforts were ongoing, Xinhua said. Xinhua reported earlier that levels of carbon monoxide -- a highly toxic, odourless gas -- had "exceeded limits" at the mine. Some of those trapped underground were in "critical condition", the earlier report said.

Shanxi, one of China's poorer provinces, is the country's coal-mining capital. Mine safety in the country has improved in recent decades, but accidents still occur frequently in an industry where safety protocols are often lax. China is the world's top consumer of coal and the largest greenhouse gas emitter, despite installing renewable energy capacity at record speed.

## Israeli airstrikes on southern Lebanon kill 10, including paramedics and a child

BEIRUT. (Agency)

Israeli airstrikes on southern Lebanon Friday killed 10 people, including six paramedics and a Syrian girl, Lebanon's Health Ministry said, the latest in near-daily attacks from both sides that have not stopped despite the fragile, US-brokered ceasefire in the Israel-Hezbollah war. The first strike hit the village of Hanouiyeh, killing four paramedics working for Hezbollah's Islamic Health Association and wounding two others including one paramedic, the ministry said.

Another strike Friday morning on the village of Deir Qanoun al Nahr in the coastal Tyre province killed six people, including a Syrian child and two paramedics from the Al-Risala Scouts Association, a paramedic group affiliated with Hezbollah's ally, the Amal movement, the ministry said. An additional six people were injured, including three paramedics and a Syrian woman.

The Health Ministry said the two attacks "violated" international law. On Thursday, the World Health Organisation reported 169 confirmed attacks on healthcare workers and facilities in Lebanon, resulting in 116 deaths, since the latest Israel-Hezbollah war began.

The Israeli military said it struck several Hezbollah infrastructure sites in the area of Hanouiyeh where Hezbollah members were present. It said that it is examining the claim that several uninvolved individuals in the area, who were not the targets of the strike, were harmed, adding that in the area of the strike, steps were taken to evacuate the population. Before the strikes, steps were taken to mitigate harm to civilians, including the use of precise munitions and aerial surveillance, according to the military.

## WHO chief says Ebola is spreading rapidly in Congo, upgrades risk assessment

BUNIA. (Agency)

The World Health Organization chief said Friday that the Ebola outbreak in Congo is spreading rapidly and now poses a "very high" risk there, as a lack of medical resources and anger among the population hamper the response in a vulnerable and conflict-ridden region. WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk of global spread remains low, but that the U.N. health agency was revising upward its assessment of the risk within Congo from its previous categorization of "high."

The WHO chief noted that 82 cases have been confirmed in Congo, with seven confirmed deaths, though he said the outbreak is believed to be "much larger." He said there are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.

Supplies were being rushed to Ituri province in the northeastern corner of the country, where the illness has been spreading for weeks in areas where many people have been displaced by armed conflict.

Frontline medical staff have struggled with a lack of resources and, in some cases, pushback due to what has been characterized as misinformation or situations where medical policy has clashed with local customs such as burial rites.

## Trump 'seriously considering' fresh strikes on Iran amid faltering truce talks

Trump met his senior national security team on Friday to discuss the Iran war as Pakistan Army chief Asim Munir and a Qatari delegation arrived in Tehran for last-ditch talks aimed at securing a deal.

World. (Agency)

United States President Trump is "seriously considering" launching fresh military strikes against Iran if last-minute diplomatic efforts fail to produce a breakthrough, according to US officials cited in a report by Axios. The assessment came after Trump convened a high-level meeting with his senior national security team on Friday morning to review the Iran conflict and possible next steps.

The discussions reportedly included Vice President JD Vance, Defense Secretary Pete Hegseth, CIA Director John Ratcliffe, White House chief of staff Susie Wiles and other top officials, with a focus on both the state of negotiations and military contingency planning.

Sources familiar with the talks said the President was briefed on multiple



scenarios, including options that would come into play if ongoing negotiations collapse. The White House later adjusted his weekend schedule following the meeting, signalling the sensitivity of the situation. The diplomatic tracks are still active but fragile. Pakistan's military chief, Field Marshal Asim Munir, is currently in Tehran in what officials describe as a last-ditch mediation effort to narrow differences between Washington and

Tehran. A Qatari delegation has also arrived in the Iranian capital to support ongoing negotiations.

Munir is expected to meet Gen. Ahmad Vahidi of the Islamic Revolutionary Guard Corps, a key figure in Iran's security establishment. Officials involved in the process describe the talks as stalled and slow-moving. Draft proposals are being exchanged, but progress remains limited and gaps on core issues persist.

A US official described the negotiations as 'agonising', saying documents were "going back and forth every day" without significant movement. Iranian state-linked outlets, meanwhile, have acknowledged that the discussions continued but maintained that no agreement is within reach. The IRGC-affiliated Tasnim news agency quoted a source saying talks over disputed issues remain underway but have

produced no final outcome, with current efforts focused narrowly on ending the war.

Tehran is also reviewing a fresh US proposal, transmitted earlier this week and described by one source to Axios as a final offer, which reportedly warned that rejection could trigger renewed military action. Inside the Trump administration, frustration appeared to have grown over the pace of diplomacy. Two people familiar with the President's thinking told Axios that his mood has shifted over recent days from cautious patience to growing impatience with Iran's negotiating stance. Earlier in the week, Trump told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that he still wanted to give diplomacy another chance. By Thursday night, however, he was reportedly leaning toward ordering a strike.

## Indian-origin man sentenced in UK to nearly 10 years over 8 million drugs plot

world. (Agency)

An Indian-origin man is among five gang members jailed in the UK for a total of 84 years for their involvement in what the Metropolitan Police described as a large-scale drugs conspiracy. Jagjit Singh, a 30-year-old from Birmingham, was sentenced to 10 years and six months for his role within a major organised crime group responsible for importing and supplying Class A banned drugs worth millions of pounds into London.

Over the course of the investigation, more than 300 kilograms of cocaine and more than 60 kilograms of heroin, with an estimated wholesale value of almost 8 million pounds in total were seized. The gang members were sentenced at Kingston Crown Court in south-west London on Thursday to prison terms ranging from 14 to 26 years each.

Singh had previously pleaded guilty on the first day of trial in October last year. "This case has centred on a criminal venture planned on a gigantic

commercial scale which would have likely caused violence and destruction on our streets," said Detective Constable Leon Ure from the Met Police's Specialist Crime unit, who led the investigation.

"These offenders organised a significant drug line into London and the



surrounding counties over a prolonged period of time. If people wonder why we are so relentless in going after those involved in drug supply, it's because this criminality fuels violence and rips families and communities apart," he said. The sentencing this week follows what the police force said was a

"complex" investigation into the organised criminal network responsible for importing and distributing significant quantities of cocaine and heroin across the UK.

"We are very grateful to our partners for their assistance. Our coordinated response has resulted in the disruption of a major threat to public safety and has taken this group of criminals off our streets," added Detective Constable Ure. The gang used a sophisticated method involving legitimate haulage routes and so-called "ghost warehouses" to move drugs from mainland Europe into the country.

Lorries arriving at UK ports would divert from their legitimate delivery routes to covert storage sites where drugs were secretly offloaded before the lorries continued to their intended destinations. Drugs that were found hidden at the warehouses would be removed, repackaged and distributed onward. Men flew in from Poland specifically to assist with unloading and onward supply, often using hired.

## Want Green Card? US says leave country first, re-enter with immigrant visa

world. (Agency)

In a move likely to hit thousands of Indians waiting for US permanent residency, the Trump administration on Friday announced that migrants seeking Green Cards will have to leave America and apply from their home countries instead of staying in the US during the process.

Under new guidance issued by US Citizenship and Immigration Services (USCIS), migrants seeking adjustment of status for a Green Card will now generally have to apply from their home countries instead of remaining inside the US during the process.

A Green Card is an official identification card that gives foreign nationals permanent residency rights in the US.



A Green Card holder can live anywhere in the US, work for most employers, study in the US, travel in and out of the country (subject to rules)

and eventually apply for US citizenship if eligible.

From now on, an alien who is in the US temporarily and wants a Green Card must return to their home country to apply, except in extraordinary circumstances," USCIS spokesman Zach Kahler said.

The move could significantly impact international students, H-1B workers and tourists currently residing in the US who had hoped to transition to permanent residency without leaving the country. "We're returning to the original intent of the law to ensure aliens navigate our nation's immigration system properly," Kahler said.

## We're not there yet: Rubio says more work needed as Iran cites deep differences

**Pakistan Army chief Asim Munir arrived in Tehran as Pakistan and Qatar stepped up mediation with Iran and the United States. The renewed push comes amid unresolved disputes over uranium and the Strait of Hormuz, with markets remaining on edge.**

World. (Agency)

Pakistan Army chief Field Marshal Asim Munir arrived in Tehran on Friday as diplomatic efforts to end the Iran conflict intensified, while US Secretary of State Marco Rubio cautioned that negotiations were still far from a breakthrough despite some progress in talks with Tehran. "We're not there yet," Rubio told reporters after a

Nato ministers' meeting in Sweden, underscoring the uncertainty hanging over the latest diplomatic push involving Pakistan, Qatar and the United States.

Iran, however, signalled that major hurdles remain, with foreign ministry spokesman Esmail Baghaei describing differences with Washington as deep and significant.

**PAKISTAN, QATAR STEP UP MEDIATION**

Munir's visit came as Pakistan expanded its mediation role between Tehran and Washington. Earlier in the day, Pakistani Interior Minister Syed Mohsin Naqvi held another round of talks in Tehran with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi, according to Iran's semi-official Tasnim news agency. At the same time, Qatar dispatched a negotiating team to the Iranian capital in coordination with the United States, a source familiar with the

matter told Reuters.

The renewed diplomacy comes six weeks into a fragile ceasefire after months of conflict involving Iran, the United States



and Israel.

**RUBIO WARNS OF UNRESOLVED ISSUES**

Rubio acknowledged that negotiators had narrowed some gaps but stressed that critical disagreements remained

unresolved. "There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it," Rubio told reporters. "There's more work to be done. We're not there yet. I hope we get there."

Among the key sticking points are Iran's stockpile of highly enriched uranium and Tehran's control over the Strait of Hormuz, through which roughly a fifth of the world's oil and liquefied natural gas supplies pass.

Rubio reiterated Washington's opposition to Iran's proposed tolling system for ships using the strait, calling the idea "unacceptable." "We're dealing with a very difficult group of people, and if it doesn't change, then the president's been clear he has other options," he added. He

also said the US had not asked Nato for military assistance in the Strait of Hormuz, though contingency planning remained necessary if Iran refused to reopen the waterway fully.



NEWS BOX

Sabalenka cuts short media duties in protest against French Open prize money

CHENNAI. (Agency)

World number one Aryna Sabalenka cut short her French Open media duties on Friday as part of a coordinated protest by leading players over Grand Slam prize money distribution. The Belarusian was among several top stars who adhered to a self-imposed 15-minute limit on press obligations ahead of the tournament in Paris.

The protest reflects growing dissatisfaction among players, who believe the four Grand Slam tournaments should allocate a larger share of their overall revenue toward prize money, benefits, and player representation in key decision-making areas.Sabalenka, one of the most vocal figures in the ongoing discussions, limited her media interaction to a brief five-minute interview with the host broadcaster followed by a 10-minute press conference with print reporters.“I’m here to talk to you because I have respect for you guys,” Sabalenka said. “We just wanted to make our point and we are united, 15 minutes is better than zero.”

The symbolic 15-minute cap was designed to



highlight the fact that the French Open currently allocates roughly 15% of its revenue toward prize money. The strategy was reportedly communicated to most of the top 200 singles players, although participation in the protest remained voluntary.“As I said a thousand times today, I have huge respect, but we know what’s happening here, so thank you so much,” she added before ending the English-language portion of her media session to accommodate reporters from Belarus.Several high-profile names, including men’s world number one Jannik Sinner and four-time French Open champion Iga Swiatek, also followed the “work-to-rule” directive during Friday’s media day.

GROWING PUSH FOR REVENUE SHARE

The coordinated action marks another escalation in the wider conversation around revenue sharing in professional tennis. Leading players on both the ATP and WTA tours have increasingly argued that Grand Slam events generate enormous commercial income while players receive a comparatively limited share of the profits.

Carrick at the wheel: Another false dawn like Solksjaer, or a new era for Man United?

Michael Carrick is finally going to be given a fair crack at Manchester United as he has been made the new full-time head coach. Can Carrick continue his fine start and prove that it isn't another false dawn at the club?

New Delhi. (Agency)

And so it begins. A new era at Manchester United. Or perhaps, more fittingly, the continuation of one, as Michael Carrick becomes the new head coach, not manager, of the 13-time Premier League champions. When United decided to part ways with Ruben Amorim, it felt as though the club was bracing for yet another implosion. It is never a good sign when a tactician publicly questions the board before walking away, and Amorim’s departure left a dark cloud hanging heavily over Old Trafford.Darren Fletcher’s brief spell in charge did little to lift the gloom as United crashed out of the FA Cup, leaving them with just 39 matches across the season.For a club of United’s stature, that was an almost unimaginable reality. Yet, for many fans, it had become an all-too-familiar story over the years. Then came Carrick. Quiet, composed, understated, much like the midfielder he was during his playing days. Never flashy, never desperate for the spotlight, just a man who understood balance, control and responsibility.From the moment he arrived at United in July 2006, Carrick was rarely the headline act. He simply did his job, slipped under the radar, and prepared for the next battle.Perhaps that is why Cristiano Ronaldo once wrote a heartfelt message for him during his first spell as United’s caretaker boss after Ole Gunnar Solksjaer was sacked.The task back then was straightforward, to steer United away from disaster in a season that looked destined to sink without resistance. Then came the tests: Manchester City, Arsenal, Chelsea and Liverpool. This was part of 11 wins in his 16 games.

All beaten. Some emphatically.

And now comes the real question: can Carrick build something lasting? At a club like United, success is never judged in moments. It is measured in trophies.



BRINGING BACK EXCITING FOOTBALL

“You want to win games, it goes without saying, we want to win games. There’s different ways of doing it, of course, different scenarios, different situations in games that [mean] you might have to play a certain way.”“But I think for me it’s [about] working with the players. I love working with the players and helping them get better individually, which, hopefully, will help the team improve and [I want to] be there to support them. I’m one of them, we’re all in it together, and I think it’s important that we all look after each other.”“But I know it comes down to results. Hopefully, we can play a really exciting type of football and be positive and express and bring excitement. I want to be off my seat. I want to be enjoying watching the boys play, and results obviously need to come with that.”“You can feel my kind of enthusiasm for it, because I’m buzzing to get started and see what we can do.”These were Carrick’s words while speaking on the Inside Carrington podcast about the football he wanted United to play. More importantly, he has stayed true to that vision.Until May 8, United had scored 26 goals under him, boasting a shot conversion rate of 13.9 percent — the best in the league since his arrival. They had also conceded just 16 goals, several of them coming in tense contests like the Fulham clash and the dramatic 2-2 draw away at Bournemouth.

Kavya Maran's priceless reaction to Krunal Pandya's bouncer takes spotlight: Watch

New Delhi. (Agency)

The IPL 2026 match between Sunrisers Hyderabad (SRH) and Royal Challengers Bengaluru (RCB) on Friday night had plenty of big hits. But a reaction from the stands stole the show on social media. Sunrisers Hyderabad CEO Kavya Maran went viral for how she reacted to RCB bowler Krunal Pandya.

Krunal is known for trying different things when he bowls. This season, he has been mixing up his pace. Sometimes, instead of standard spin, he bowls a fast ball or throws in a surprise short bouncer to catch the batsman off guard.

The incident happened during the 17th over of the first innings when SRH batter Nitish Kumar Reddy was on strike. Krunal decided to try a surprise tactic and fired in a sharp, fast bouncer. The delivery went so high that the umpire actually called it a wide, meaning Krunal had to bowl the delivery over again.When the ball went over the batter’s head, the cameras immediately



showed the VIP box. Kavya Maran looked completely shocked by the unexpected delivery. The clip quickly went viral on social media, with fans loving her passion for the game. Even though his bowling

IPL Play Of The Day: Heinrich Klaasen makes Hazlegod look human in Uppal carnage



New Delhi. (Agency)

For RCB, Josh Hazlewood has been a cheat code. When they need wickets in the powerplay, middle or the death, the Australian pacer has been the man they turn to. He had 22 wickets in 12 matches when they went to claim the IPL title in 2025 and has 12 scalps to his name from 11 matches this time around. This made the Bengaluru fans fondly call him 'Hazlegod' purely based on his skill and the way he functioned with the ball.

But on Friday, May 22, Heinrich Klaasen decided to take down Hazlewood in what was carnage at the Uppal stadium and show that he was also a mortal in the end. Klaasen has been enjoying a purple patch this season, not with his usual destructive ways, but with a measured approach.He said that his mindset has changed and he wasn’t trying to strike at 300 this season. But against RCB, he decided to go back to his old ways and unleash his fury on the RCB bowlers and particularly Hazlewood.Now, many moments could have easily become the Play Of The Day for the SRH vs RCB clash. Ishan Kishan continuing his fine form against Bengaluru and the way the Hyderabad bowlers cleverly used slower deliveries to nullify RCB’s firepower are worthy shouts.

But just for his pure brilliance, Klaasen takes home the honour for the match.

KLAASEN SCARES RCB BOWLERS

SRH went out to score big and that was something Pat Cummins said at the toss. Travishek got going and put on 45 runs for the first wicket in four overs.Abhishek Sharma and Kishan added 52 in the next 4.2 overs to push the run-rate even further. Abhishek scored a fine fifty but didn’t waste time and allowed Klaasen to come in.But something seemed to be off. Klaasen wasn’t timing the ball well and suddenly the pressure seemed to build on the South African batter.

Should RCB have gone for the win vs SRH? Qualifier 1 priority in 255 chase spilt fans

Kolkata. (Agency)

A Royal Challengers Bengaluru may have secured the bigger prize from Hyderabad on Friday night, but the manner in which they approached their 256-run chase against Sunrisers Hyderabad has now opened up an entirely different debate among fans online.

After losing by 55 runs at the Rajiv Gandhi International Stadium, RCB still managed to finish inside the IPL 2026 top two and seal their place in Qualifier 1 thanks to Net Run Rate. In tournament terms, that is massive because a top-two finish gives teams two opportunities to reach the IPL final.But while the qualification math worked perfectly for RCB, many fans were left frustrated watching the defending champions seemingly shift focus midway through the chase from winning the match to simply protecting their qualification scenario.

And social media immediately split into two sides.One section questioned why RCB appeared to back away from the chase after a flying start, especially on a batting surface where SRH themselves had crossed 250 comfortably. The other side argued that

once Virat Kohli got dismissed and the risk of a batting collapse emerged, protecting Qualifier 1 became the smarter cricketing decision.HOW RCB APPROACHED 255 CHASE VS SRH

Venkatesh Iyer came out aggressively and smashed 44 off just 19 balls while Virat



Kohli looked positive early on. RCB raced to 75 runs in the powerplay despite losing two wickets, and for a brief period, SRH were being forced to think defensively. But the momentum shifted sharply after the powerplay.

Kohli departed for 15 and suddenly the run flow completely slowed down. In a chase of 256, RCB surprisingly took until the 13th

over to even reach the 120-run mark, and from there onwards, the innings increasingly looked more focused on qualification security than genuinely threatening SRH’s total.Rajat Patidar and Krunal Pandya added 84 runs together off 57 balls, which in isolation is not a poor partnership at all. But in the context of such a gigantic chase, it never truly created scoreboard pressure on SRH.

Patidar completed another half-century and ended with 53 off 37 balls, but it was one of those knocks the RCB captain himself probably would not look back at too fondly despite the milestone. A strike rate of 143.24 in a 250-plus chase felt unusually subdued for someone who has built his entire season around fearless intent and momentum-shifting batting.The delayed arrival of hitters like Tim David and Jitesh Sharma only added more fuel to the online debate.Many RCB supporters defended the approach by pointing towards the bigger picture. Their argument was simple: RCB did begin the chase seriously, but once Kohli got out, the batting lineup carried the danger of collapsing completely under scoreboard pressure.

online appears to show Kohli completely ignoring the customary post-match handshake with the Australian left-hander. While Kohli warmly shook hands with SRH captain Pat Cummins, Abhishek Sharma, and Ishan Kishan, his swift bypass of Head became the talk of the night.

HOW THE KOHLI-HEAD DRAMA UNFOLDED

The post-match snub wasn't an isolated incident; the friction had been building all evening. During the first innings, Kohli uncorked an extraordinarily animated celebration when Head was cleaned up by Rasikh Salam Dar for 26.

The verbal battle peaked during RCB’s steep chase of 256. Kohli was seen exchanging heated words with Head and even gestured aggressively, challenging the Australian to come into the attack and try his luck with the ball. In a cinematic twist, Head did come on to bowl later in the innings and promptly picked up the massive wicket of RCB



skipper Rajat Patidar, who was going strong on 56 off 39 deliveries.

ISHAN KISHAN, ABHISHEK SHARMA POWERS SRH

Powered by explosive half-centuries from Ishan Kishan, who smashed a dazzling 79 off 46 balls to claim the Player of the Match honours, and Abhishek Sharma, who blasted 56 off just 22 deliveries, SRH piled up a mammoth 255 for 4. Heinrich Klaasen added late fireworks with a 24-ball 51. In response,

a disciplined Hyderabad bowling unit choked RCB’s momentum, restricting the visitors to 200 for 4 despite Patidar’s fighting fifty and Krunal Pandya’s unbeaten 41.

IPL 2026 PLAYOFFS: TOP 3 CONFIRMED

Despite the crushing defeat, RCB had a major silver lining. Thanks to their Net Run Rate (NRR) cushion, they managed to hold onto their spot in the top two of the standings, keeping them in a prime position for the knockouts.

As the league stage hits its business end, RCB, Gujarat Titans, and SRH all sit level on 18 points, with NRR deciding their final playoff seeding. While the top three spots are now officially locked in, the battle for the fourth and final playoff position remains wide open, with the Rajasthan Royals, Punjab Kings, and Kolkata Knight Riders all fighting to sneak into the knockouts.

ISL clubs urge 'no binding decision' on commercial partner at AIFF SGM



NEW DELHI. (Agency)

The Indian Super League (ISL) clubs have urged the All India Football Federation (AIFF) and its General Body members against taking a decision on the long-term commercial rights model when it convenes in Kolkata today for the Special General Meeting (SGM).

In a late-night email to AIFF president Kalyan Chaubey and Deputy Secretary General M Satyanarayan, FC Goa CEO Ravi Puskur -- and rest of the ISL clubs -- reiterated their concerns regarding the proposed commercial structure while "requesting for a collaborative engagement."

On Friday, ISL clubs had two virtual meetings with senior AIFF officials over the way forward but no solution was found. The two parties are warring over the commercial rights partner.AIFF are in favour of UK-based Genius Sports -- who have bid for the commercial rights -- over a 15-20 year period. The teams, however, have proposed a club-led model with Genius Sports' scope limited to data and technology partner.

In a 13-point email, Puskur and clubs requested that "no binding decision be taken at the Special General Meeting scheduled for tomorrow [May 23]. The Clubs remain willing and available to continue engaging constructively with the AIFF and Genius Sports to arrive at a collaborative and financially sustainable framework that protects the interests of all stakeholders and, most importantly, secures the future of Indian football."The clubs once again said they had not been provided detailed financial projections, revenue assumptions or long-term modelling over the Genius Sports-led model. The UK-based company has bid Rs 64.4 crore annually with 5% increase for the rights of the ISL and the Federation Cup.East Bengal, Mohun Bagan share spoils in dramatic 1-1 ISL Kolkata DerbyThey argued that while AIFF and Genius Sports appear financially protected under the structure, clubs — who bear the operational costs of running professional football through player salaries.



# Shanaya Kapoor

## Wishes Suhana Khan On Her 26th Birthday, Says 'My Su, Love You For Life'

Actress Shanaya Kapoor gave a glimpse into her close friendship with actress Suhana Khan as she shared a beautiful birthday wish for the latter, through a post on her social media. Taking to her social media account, Shanaya Kapoor posted a picture featuring herself posing with Suhana against the backdrop of colourful European-style buildings and yachts. Shanaya captioned the picture as, "Happy birthday my su. Love u for life," followed by a pink heart emoji. Suhana reshared the heartfelt post on her social media handle.

Talking about Suhana Khan and Shanaya Kapoor, the two girls are known to share a close bond and are often seen vacationing and partying together along with their other bestie and Bollywood actress Ananya Panday. Their friendship dates back to childhood as the families of their respective parents, Shah Rukh Khan, Sanjay Kapoor, Chunky Panday have remained close and family friends over the years. On the work front, Suhana made her acting debut with Zoya Akhtar's 'The Archies', which premiered on OTT in 2023. The film also marked the debut of many star kids including Khushi Kapoor and Agastya Nanda. Suhana will next be seen sharing screen space with her father Shah Rukh Khan in the upcoming film 'King'.

Meanwhile, Shanaya Kapoor made her Bollywood debut with 'Aankhon Ki Gustaakhiyan'. The actress has been receiving Great reviews for her performance in her recently released movie 'Tu Yaa Main.' She is also gearing up for her pan-India film, "Vrushabha", opposite South superstar Mohanlal.



Shanaya Kapoor and Suhana Khan posing together in front of a waterfront with colorful buildings and yachts.



# Sonam Bajwa

## Warns Against 'Wiping Dogs Off Streets' As Punjab Launches Massive Stray Dog Operation

As Punjab rolls out a large-scale campaign to tackle the growing stray dog crisis, the debate around public safety versus animal welfare is becoming increasingly intense. With concerns mounting across the state over rising dog-bite cases, the administration's latest move has now sparked reactions from public figures and animal rights advocates alike. Actor Sonam Bajwa has urged the Punjab government to ensure that the ongoing crackdown on stray dogs does not turn into what she described as an inhumane exercise. Addressing Punjab Chief Minister Bhagwant Mann through social media, the actor appealed for a more compassionate and structured approach while implementing the Supreme Court's recent directives on stray animal management.

Reacting to the discussions surrounding the state's campaign, Sonam said many people were misreading the court's observations. "The Court spoke about regulated removal from sensitive public spaces along with sterilisation, vaccination and sheltering — not wiping dogs off the streets," Bajwa stated in her social media post. The actor also questioned whether the current system had the capacity to responsibly handle such an extensive operation. Raising concerns over inadequate shelter facilities and rehabilitation mechanisms, she wrote, "Where are the shelters? Where is the infrastructure?"

"This absolutely cannot become a death sentence for voiceless animals. Public safety matters. Human lives matter. But compassion and responsibility matter too," she added.

Sonam further stressed the need for long-term planning instead of relying only on removal drives. According to her, sustainable solutions would require cooperation between animal welfare organisations, veterinarians, municipal authorities and public safety experts.

She also highlighted the importance of sterilisation programmes, vaccination campaigns and proper shelter systems if the state genuinely wants to reduce the stray dog population in a safe and organised manner. "How we treat the voiceless ultimately reflects who we are as a society," she added.



## Is Kangana Ranaut Married? Truth Behind Viral Mangalsutra Video Revealed



Kangana Ranaut's fans were left surprised on Thursday evening when a video of the actress-turned-politician surfaced on social media in which she was seen wearing a mangalsutra. In the viral clip, Ranaut was seen walking with her security personnel when her mangalsutra grabbed everyone's attention. In no time, the video went viral, with netizens wondering if the actress had secretly gotten married.

No, Kangana Ranaut is not married. In fact, the actress' viral video is her look from her upcoming movie, Queen 2. Reportedly, Ranaut has already started shooting for the film, which is tentatively titled Queen Forever.

Released in 2013, Queen was directed by Vikas Bahl, starring Kangana Ranaut. The film follows Rani Mehra, a shy young woman from Delhi whose fiancé calls off their wedding just before the ceremony.

Instead of staying heartbroken, Rani decides to go alone on her planned honeymoon to Paris and Amsterdam. During her journey, she discovers independence, confidence and a new outlook on life. The movie also features Rajkumar Rao, Lisa Haydon and Mish Boyko. The film became both a critical and commercial success, winning several awards, including the National Film Award for Best Hindi Film and Best Actress for Kangana Ranaut.

Meanwhile, Kangana Ranaut will soon also be seen in Bharat Bhagya Viddhaata. The film is a cinematic tribute to the unsung heroes, and it will be helmed by director-writer Manoj Tapadia. Reportedly, Kangana Ranaut will portray the role of a staff nurse in the film, which seeks to highlight the vital role played by such individuals who work relentlessly behind the scenes during the 26/11 Mumbai Attacks. This movie will hit theatres on June 12, 2026.

## Pooja Bhatt Drops Old Photos With Aamir Khan, Says 'Someday I Will Share The Story Behind...'



Actress and filmmaker Pooja Bhatt recently sent her fans into a nostalgic frenzy after she shared a major throwback picture with superstar Aamir Khan from one of their old photoshoots. The vintage pictures were clicked by celebrated photographer Gautam Rajadhyaksha.

Sharing the photographs on her social media, Pooja wrote, "Someday I will share the story behind these impromptu photos shot on Gautam Rajadhyaksha's balcony, in his sprawling home on Hughes road. But not yet.. Not just yet." In the pictures, a young Aamir Khan and Pooja Bhatt are seen twinning in white outfits while posing candidly for the camera.

Talking about Pooja Bhatt and Aamir Khan, the two shared screen space in the 1991 romantic drama 'Dil Hai Ke Manta Nahin', directed by Mahesh Bhatt. The film, which also starred Anupam Kher, became a huge hit and is still remembered as one of Bollywood's most loved romantic films. In the movie, Aamir played the role of 'Raghu Jetley', a kind-hearted journalist, while Pooja essayed 'Pooja Dharamchand', a rich runaway heiress.

Talking about Pooja Bhatt, the actress made her acting debut with 'Daddy' in 1989, directed by her father Mahesh Bhatt. The film also starred veteran actor Anupam Kher.

For the uninitiated, Aamir Khan made his debut as a lead actor with 'Qayamat Se Qayamat Tak' in 1988 opposite Juhi Chawla. On the work front, Pooja Bhatt was recently seen in projects like Bombay Begums and Bigg Boss OTT 2.

Meanwhile, Aamir Khan has lately been supporting his son Junaid Khan, who stepped into Bollywood recently. The actor was seen promoting Junaid's film 'Ek Din', which also stars Sai Pallavi. The late Gautam Rajadhyaksha who was touted as one of India's most iconic celebrity photographers, was known for capturing timeless portraits of Bollywood stars.